।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

● वर्ष-5

● अंक-217

रायपुर, मंगलवार
28 अप्रैल 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› इसरो के यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम ...

बंगाल में थमा चुनावी शोर

भाजपा बोली- टीएमसी ने घुसपैठियों का गढ़ बनाया; ममता ने राज्य को बांटने का लगाया आरोप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार सोमवार को समाप्त हो गया। यह चुनाव घुसपैठ, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भाजपा और टीएमसी के बीच तीखी राजनीतिक लड़ाई से प्रभावित रहा। दोनों दलों ने 142 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से कई वादे किए। इस जोरदार प्रचार अभियान के दौरान, भाजपा नेतृत्व ने सत्ताधारी टीएमसी पर पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों का गढ़ बनाने का आरोप लगाया। वहीं, ममता बनर्जी ने भगवा दल पर विभाजनकारी राजनीति करने, राज्य को बांटने का प्रयास करने और मछली व अंडे के सेवन के हतोत्साहित करने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई भाजपा नेताओं ने राज्य में प्रचार किया। उन्होंने टीएमसी पर कानून व्यवस्था बिगड़ने, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों, राजनीतिक अशांति, घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर हमला किया। मोदी ने मतुआ समुदाय से संपर्क साधा और उनसे नागरिकता अधिनियम पर टीएमसी केझूठसे गुमराह न होने का आग्रह किया। उन्होंने सभी शरणार्थियों को देश में स्थायी निवास का आश्वासन दिया। शाह ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर पशु तस्करी रोकने और मवेशियों की रक्षा के लिए एक विशेष दस्ता बनाया जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर तस्करों की मदद करने का आरोप लगाते हुएगुंडा राजऔरसिंडिकेट राजखत्म करने का वादा किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक पूर्व विधायक हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद का निर्माण शुरू करने की अनुमति दी गई थी। शाह ने 4 मई के बादभाइपो करखत्म करने और महिलाओं व बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 रुपये मासिक भत्ता तथा राज्य परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी वादा किया।

टीएमसी नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। इनमेंहर बैंक खाते में 15 लाख रुपये और सालाना दो करोड़ नौकरियांजैसे वादे शामिल हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के बाद अपनी एक रैली में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने सत्ता बरकरार रखने का विश्वास व्यक्त किया। बनर्जी ने शाह पर चुनाव के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ उनकेउल्टा लटका देंगेवाले बयान को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने एक संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाया और कहा कि उनकी पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।

उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाने पर भी चिंता जताई और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को कथित ज्यादतियों के खिलाफ चेतावनी दी।

मोदी ने लिखा पत्र

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों के नाम एक पत्र और एक ऑडियो संदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल के पूरे चुनाव अभियान के दौरान मुझे अपने परिवारजनों का जो अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है, उसने एक नई ऊर्जा से भर दिया है। यहां की युवाशक्ति हो या नारीशक्ति, हमारे किसान भाई-बहन हों, श्रमिक या फिर कारोबारी, सभी विकसित बंगाल के लिए संकल्पित हैं। मैंने इस पत्र में उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यवासियों के नाम एक ऑडियो संदेश भी जारी किया है, जो हिंदी और बंगाली भाषा में अलग-अलग जारी किया गया है।

पीएम मोदी ने बताया कि प्रथम चरण के मतदान ने इतिहास रचा है। उन्होंने बंगाल के लोगों से 29 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आह्वान किया। यह लोकतंत्र के मंदिर में विजय की ध्वज फहराने का बेहतरीन अवसर है।

बंगाल चुनाव में एक्शन मोड

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को मिली बड़ी ज़िम्मेदारी

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के प्रयास में, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश कैडर के जाने-माने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अजय पाल शर्मा को मतदान के अहम दूसरे चरण से पहले चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

यह कदम 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के दूसरे चरण से ठीक पहले उठाया गया है, जिसमें कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के 142 निर्वाचन क्षेत्र शामिल होंगे। शर्मा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कैडर के 2011 बैच के ढ्ढक्क अधिकारी हैं और मूल रूप से लुधियाना के रहने वाले हैं, अपनी सख़्त पुलिसिंग शैली के लिए जाने जाते हैं और उन्हें पुलिस बल के सबसे काबिल अधिकारियों में से एक माना जाता है। अपने करियर के दौरान वे कई जोखिम भरे ऑपरेशनों से जुड़े रहे हैं।

सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम

चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए हैं, जिसके तहत पश्चिम बंगाल के सात ज़िलों में केंद्रीय बलों की 2,321 कंपनियाँ तैनात की गई हैं। इसके अलावा, चुनावी प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए 142 सामान्य पर्यवेक्षक, 95 पुलिस पर्यवेक्षक और 100 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रियल-टाइम निगरानी के लिए कैमरों से लैस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोलकाता में सबसे ज़्यादा तैनाती देखने को मिली है, जहाँ शहर में केंद्रीय बलों की 273 कंपनियाँ तैनात की गई हैं।

रायपुर.। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण स्थित राम मिलेंगे आश्रम, तेंदुवा धाम कुरियारी में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा में शामिल हुए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ आश्रम पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया।

खाड़ी मिशन पर अजित डोभाल, यूएई राष्ट्रपति से मिले

नईदिल्ली। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जिस वक्त संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मुलाकात कर रहे थे। उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो 77 सालों में पहली बार हुआ है। खबर है कि इजराइल ने इतिहास में पहली बार अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को संयुक्त अरब अमीरात की सुरक्षा में खड़ा कर दिया है। यह पहला मौका है जब 77 सालों में इजराइल ने अपने किसी एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम को किसी दूसरे देश की सुरक्षा में खड़ा कर दिया। इजराइल ने सुन्नी संयुक्त अरब अमीरात को शिया ईरान से बचाने के लिए अपना आयरन डोम तैनात कर दिया। यानी ईरान जंग के बीच भारत संयुक्त अरब अमीरात की कूटनीतिक मदद कर रहा है। वहीं इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात को अपने हथियारों से बचा लिया है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की सुरक्षा के लिए भारत और इजराइल का खड़ा होना कोई सहयोग नहीं बल्कि बहुत बड़ा प्रयोग है। इस खबर ने ईरान, पाकिस्तान और पाकिस्तान से डिफेंस डील करने वाले सऊदी अरब को कुछ हद तक हिला कर रख दिया है। सऊदी अरब की सुरक्षा में पाकिस्तान की चवन्नी छाप सेना खड़ी है तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात में इजराइल ने हथियार उतार दिए हैं।

यह खबर कैसे खाड़ी देशों की पावर इक्वेशन को बदल देगी और भारत को कितनी ताकत देगी वह अब आपको बताते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब ईरान जंग को दो हफ्ते ही हुए थे। उस समय ईरान ने खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए थे। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले संयुक्त अरब अमीरात पर ही किए थे। उस वक्त संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने फोन उठाया और नेतन्याहू को मिलाया। बातचीत के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन इसके बाद ईरान ने जब संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर 563 मिसाइलें और 2256 ड्रोन दागे तो इनमें से ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ईरान भी हैरान था कि उसके हथियार संयुक्त अरब अमीरात तक कैसे नहीं पहुंच पा रहे। इसी बात का खुलासा अब हुआ है। दरअसल मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान की मांग के बाद नेतन्याहू ने इजराइली सेना को आदेश दिया कि वह पूरी आयरन डोम की बैटरी, दर्जनों इंटरसेप्टर और कई दर्जन आईडीएफ ऑपरेटर्स को यूएई की धरती पर पहुंचाएं।

वार्ता विफल होने पर हताश मुनीर लगा रहे दौड़

एथेंस । अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत में रुकावट के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में होने वाली दूसरी दौर की बातचीत शुरू ही नहीं हो पाई, जिससे इस्लामाबाद में निराशा और बेचैनी बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से राजधानी में कड़े सुरक्षा इंतजाम और लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रही, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अचानक इस्लामाबाद से लौट गए, जिसके बाद बातचीत पूरी तरह ठप हो गई। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का पाकिस्तान दौरा भी रद्द कर दिया।

प्रमुख समाचार

दिल्ली दंगों केस को साबित करने में नाकाम अभियोजन, सभी बरी

नईदिल्ली। यहां की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक व्यक्ति का अपहरण और हत्या करने के आरोपी 12 लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि चश्मदीदों के बयानों में बड़े विरोधाभास और कमजोर सहायक साक्ष्यों के कारण अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह मुशर्रफ की हत्या के आरोपी लोकेश सोलंकी, पंकज शर्मा, सुमित चौधरी उर्फ बादशाह, अंकित चौधरी उर्फ फौजी, प्रिंस उर्फ डीजे वाला, ऋषभ चौधरी उर्फ तपस, जतिन शर्मा उर्फ रोहित, विवेक पांचाल उर्फ नंदू, हिमांशु ठाकुर, साहिल उर्फ बाबू, संदीप उर्फ मोगली और टिंकू अरोड़ा के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। न्यायालय ने 21 अप्रैल के एक आदेश में कहा,अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। तदनुसार, सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।मुशर्रफ की मौत से जुड़े मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

पाकिस्तान में लश्कर कमांडर शेख अफरीदी की मौत

नईदिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के भीतर एक बार फिर खलबली मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक बेहद प्रभावशाली और सीनियर कमांडर शेख अफरीदी की एक अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सुरक्षा विशेषज्ञ इस घटना को एक सोची-समझी टारगेटेड स्ट्राइक (निशाना बनाकर किया गया हमला) मान रहे हैं।अफरीदी को ल्ढ्ढञ्ज के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी माना जाता था और माना जाता था कि वह इस इलाके में संगठन की गतिविधियों की देखरेख में अहम भूमिका निभाता था। अधिकारी उसकी हैसियत और हमले के हालात को देखते हुए इस हत्या को एक टारगेटेड स्ट्राइक मान रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में, 16 अप्रैल को लाहौर में ल्ढ्ढञ्ज के सह-संस्थापक आमिर हमजा पर भी अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया था कि 66 साल का यह नेता, जिसे हाफिज सईद के बाद संगठन के सबसे सीनियर लोगों में से एक माना जाता था।

सात सांसदों के विलय पर कानूनी लड़ाई की चेतावनी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने सात पूर्व राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को कहा कि अगर इन सांसदों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया तो पार्टी अदालत का रुख करेगी। संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सातों सांसदों द्वारा भाजपा में विलय के लिए दिया गया पत्र स्वीकार कर लिया गया, लेकिन आप की आपत्तियों और दसवीं अनुसूची (एंटी-डिफेक्शन कानून) के तहत उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सभापति ने उन सात सांसदों के पत्र को आधार बनाकर विलय स्वीकार कर लिया, जबकि हमारी आपत्ति और अयोग्यता की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया है। आप नेता ने उम्मीद जताई कि जब उनकी पार्टी का पत्र विस्तार से देखा जाएगा तो संविधान और लोकतंत्र के हित में इन सांसदों को अयोग्य ठहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी अदालत जाएगी।

समुंदर में चीन को तोड़ने उतरा भारत का दोस्त ऑस्ट्रेलिया

नईदिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो इंडोपेसिफिक क्षेत्र में इनकी ताकत को और बढ़ाने का काम करेगा। दरअसल खबर यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इस साल एक नया समुद्री सहयोग समझौता यानी कि मेरिटाइम कोऑपरेशन पैक साइन करने की तैयारी में है। यह समझौता हिंद महासागर में सुरक्षा निगरानी और सैन्य सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने साफ कहा कि भारत उनके लिए इंडोपेसिफिक में एक सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बन चुका है। यानी अब दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं। और अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेरिटाइम कोऑपरेशन पैक साइन हो जाता है तो इस क्षेत्र में दोनों ही देशों को बढ़त मिलेगी, फायदा मिलेगा और यह दोनों देश साथ मिलकर इस क्षेत्र की निगरानी कर पाएंगे। साल एक नया समुद्री सहयोग समझौता यानी कि मेरिटाइम कोऑपरेशन पैक साइन करने की तैयारी में है।

टीसीएस मामले में आरोपी निदा खान को जेल या बेल?

मुंबई । महाराष्ट्र के नासिक में स्थित आईटी कंपनी टीसीएस की स्थानीय यूनिट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने नौ अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इसकी जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाया गया है।आरोप है कि कंपनी की एक महिला कर्मचारी निदा खान अपने सहकर्मियों को इस्लामी रीति-रिवाजों का पालन करने, नमाज पढ़ने और मांसाहारी भोजन खाने के लिए दबाव डालती थी। इस केस में अब तक एक महिला ऑपरेशंस मैनेजर समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टीसीएस ने भी इन आरोपों पर सख्त एक्शन लेते हुए आरोपी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। नासिक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.जी. जोशी की अदालत में निदा खान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। सरकारी वकील अजय मिसर ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि मामले की गहराई तक जाने के लिए निदा खान की पुलिस हिरासत में पूछताछ बहुत जरूरी है।

पश्चिम एशिया में कूटनीति और टकराव दोनों चल रहे

नईदिल्ली। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच कूटनीति और टकराव दोनों समानांतर चल रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इन दिनों लगातार सक्रिय कूटनीतिक दौरों पर हैं। पाकिस्तान और ओमान की यात्राओं के बाद वह रूस पहुंचे, जहां उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि हालिया बातचीत बेनतीजा रहने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अराघची ने साफ कहा कि वाशिंगटन की अत्यधिक मांगों ने वार्ता को पटरी से उतार दिया, जबकि प्रगति की गुंजाइश मौजूद थी। उन्होंने यह भी दो टूक कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवाजाही केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अहम मुद्दा है। देखा जाये तो अराघची की यह कूटनीतिक सक्रियता रणनीतिक संदेशों से भरी हुई है। पाकिस्तान में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व और सेना प्रमुख से मुलाकात कर अमेरिका तक ईरान की तथाकथित 'रेड लाइन' पहुंचाई, जिसमें परमाणु मुद्दा और होर्मुज जलडमरूमध्य प्रमुख हैं। ओमान में भी उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। रूस पहुंचकर उन्होंने यह संकेत दिया कि ईरान अब बहुपक्षीय समर्थन के साथ आगे बढ़ना चाहता है।

दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख पूरी तरह दबाव की राजनीति पर आधारित नजर आ रहा है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि ईरान चाहे तो खुद संपर्क करे, लेकिन अमेरिका झुकने वाला नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों और आर्थिक नाकेबंदी ने ईरान की सैन्य और औद्योगिक क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान की नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी हैं और उसकी मिसाइल फैक्ट्रियों को भारी नुकसान हुआ है। देखा जाये तो ट्रंप के बयान मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझदारी नहीं दिखाता तो अमेरिका किसी भी स्थिति में जीत हासिल करेगा। लेकिन इसी के साथ उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान के भीतर मतभेद हैं और यही स्थिति आगे के घटनाक्रम को प्रभावित कर सकती है।

हालांकि ईरान ने भी उसी तीखे अंदाज में जवाब दिया है। उपराष्ट्रपति इस्माइल सघाब इस्फहानी ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान के तेल ढांचे को नुकसान पहुंचा तो चार गुना जवाब दिया जाएगा। यह बयान इस पूरे टकराव को सीधे आर्थिक युद्ध से जोड़ देता है।

इस बीच, ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भी भेजा है। रिपोर्टों के अनुसार यह दो चरणों की योजना है, जिसमें पहले युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की बात है, जबकि परमाणु मुद्दे को बाद में उठाने का संकेत दिया गया है। इसके बदले में ईरान चाहता है कि अमेरिका उसकी नाकेबंदी खत्म करे।

लेकिन यह कूटनीतिक कोशिशें जमीनी हालात से मेल नहीं खा रहीं। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले लगातार जारी हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। संघर्ष विराम के बावजूद हो रहे ये हमले स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हैं। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने का दावा किया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है। ईरानी नेताओं ने साफ कहा है कि अब युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापसी संभव नहीं है। यह सीधा संकेत है कि तेहरान इस रणनीतिक मार्ग को अपने प्रभाव के दायरे में रखना चाहता है।

ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि समुद्री सुरक्षा और फंसे हुए नाविकों की रिहाई बेहद जरूरी है। इससे साफ है कि यह संकट अब मानवीय पहलुओं को भी प्रभावित कर रहा है।ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने भी अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि केवल अमेरिका के पास ही ताकत नहीं है। उन्होंने एक प्रतीकात्मक गणितीय उदाहरण के जरिए बताया कि दोनों पक्षों के बीच शक्ति संतुलन बना हुआ है। यह बयान संकेत देता है कि ईरान खुद को कमजोर मानने को तैयार नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल भी उठ रहे हैं। एक ईरानी सांसद ने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं है और वह अमेरिका के प्रभाव में है। इसके बावजूद तेहरान इस्लामाबाद के जरिए संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी कूटनीतिक मजबूरी को दर्शाता है। उधर, समुद्री क्षेत्र में भी तनाव बढ़ता दिख रहा है।

भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया एआई वीडियो मामला, कांग्रेस ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया का एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी गलियों का पारा चढ़ गया है। सोशल मीडिया में वायरल हुए इस रील में दोनों को डेटिंग करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो को कांग्रेस के कार्यकर्ता चरित्र हनन के मामले से जुड़ा मान रहे हैं।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने वीडियो के विरोध में रैली निकाली और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने एसएसपी को दिए ज्ञापन में वैशाली नगर निवासी आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने चेतावनी दी है।साथ ही साथ आरोप लगाया है कि विपक्ष की शिकायतों पर कार्रवाई में देरी की जाती है। वहीं हंगामे के बीच एसएपी ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दो दिन का समय मांगा है। फिलहाल पुलिस वीडियो के तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है।

तीजनबाई की मौत की खबर अफवाह, परिजनों ने जताई नाराजगी कड़ी कार्रवाई की मांग की

भिलाई। अंतरराष्ट्रीय पंडवानी गायिका और पद्मविभूषण से सम्मानित तीजनबाई के निधन की झूठी खबर रविवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. इस भ्रामक सूचना ने उनके देश-विदेश में फैले करोड़ों प्रशंसकों के बीच शोक और चिंता की लहर पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के श्रद्धांजलि संदेश साझा किए जाने लगे, जिससे स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। तीजनबाई के परिजनों और सहयोगियों ने तुरंत सामने आकर इन खबरों का खंडन किया है। उनकी बहू वेणु देशमुख ने स्पष्ट किया कि माताजी पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। परिजनों ने ऐसी संवेदनहीन अफवाहों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। वेणु देशमुख ने कहा कि यह दूसरी बार है जब ऐसी झूठी खबर फैलाई गई है।उन्होंने अफवाह फैलाने वालों की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी मानसिक पीड़ा देने वाली घटनाओं पर रोक लग सके।

वर्ष भर में बस्तर संभाग में 100 प्रतिशत विद्युतिकरण का लक्ष्य

जगदलपुर। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे इस क्षेत्र में अब ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। बिजली विभाग के अनुसार संभाग के कुल 1189 गांवों में से लगभग 70 प्रतिशत गांवों में विद्युत आपूर्ति पहुंचा दी गई है, जबकि शेष 30 प्रतिशत दुर्गम और पहुंच विहीन क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार 860 गांवों में पारंपरिक बिजली पहुंचाई जा चुकी है।

वर्षभर के भीतर बस्तर संभाग के सभी गांवों को 100 प्रतिशत विद्युतिकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है, खासकर दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जैसे जिलों में, जहां भौगोलिक कठिनाइयों और कभी-कभी सुरक्षा चुनौतियों के कारण कार्य अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। बिजली विभाग के एसी केबी मैथ्यू ने बताया कि बारिश के मौसम से पहले अधिकतम गांवों तक बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बारिश शुरू होने के बाद नदी-नालों के उफान और दुर्गम रास्तों के कारण काम में बाधाएं आती हैं। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में लगातार बादल रहने या धूप की कमी के कारण सोलर पैनल की चार्जिंग भी प्रभावित होती है। उन्होने बताया कि नियद नेल्लनार योजना और धरती आबा योजनाओं का उद्देश्य अंतिम छोर तक खंभे लगाकर बिजली पहुंचाना है। जिससे ग्रामीणों को बारिश में बैटरी चार्ज की समस्या से छुटकारा मिल सके। ताकि कोई भी गांव बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे।

विधायक ने कहा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देना कांग्रेस की प्राथमिकता रही है. देश को पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने ही दिया

परिसीमन पर सियासत तेज : लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार का भाजपा पर आरोप

जशपुर। जनगणना प्रक्रिया पूरी होने से पहले परिसीमन की कोशिशों को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र की विधायक विद्यावती सिदार ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण का नहीं, बल्कि पिछले दरवाजे से परिसीमन के प्रयासों का विरोध कर रही है।

जिला कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए विधायक सिदार ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण बिल 2023 संसद से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। ऐसे में भाजपा द्वारा कांग्रेस पर महिला विरोधी होने के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शासन-प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देना कांग्रेस की प्राथमिकता रही है। महिला विधायक ने उदाहरण देते हुए कहा कि देश को पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में कांग्रेस ने ही दिया। इसके अलावा पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और पहली महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित भी कांग्रेस की देन रही हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विधायक सिदार ने कहा कि हाल ही में लोकसभा में एनडीए द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन संशोधन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर लाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में राजनीतिक झटके के बाद प्रधानमंत्री और भाजपा नेता कांग्रेस पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। कांग्रेस की प्रदेश सचिव रत्ना पैंकरा ने कहा कि देश में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की शुरुआत पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं इसी आरक्षण व्यवस्था के तहत पहली बार चुनाव लड़ा था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक सिदार ने कहा कि सरकार इस सत्र का उद्देश्य अब तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस, शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार विधानसभा के भीतर इस मुद्दे पर सरकार को कड़ा जवाब देगी।

भाजपा द्वारा कांग्रेस पर देशहित के कदमों का विरोध करने के आरोपों को खारिज करते हुए विधायक सिदार ने कहा कि आजादी के बाद देश के विकास में कांग्रेस का योगदान और बलिदान ही इन आरोपों का सबसे बड़ा जवाब है।

ओबीसी महासभा का ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन

जातिगत जनगणना की मांग

- **ओबीसी महासभा का आरोप है कि सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए जारी अधिसूचना के प्रारूप में ओबीसी के लिए कॉलम ही नहीं रखा.**

सूरजपुर। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने मोर्चा खोल दिया है. महासभा के सैंकड़ों कार्यकर्ता ऊंचडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन का सांकेतिक घेराव करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा का आरोप है कि सरकार द्वारा वर्ष 2027 की जनगणना के लिए जारी अधिसूचना के प्रारूप में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए तो कॉलम निर्धारित किया गया है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए कोई अलग कॉलम नहीं रखा गया है। महासभा का कहना है कि इससे देश की एक बड़ी आबादी जातिगत आधार पर जनगणना में शामिल होने से वंचित रह जाएगी।

हमारी मांग है कि जनगणना के प्रारूम में अलग से हमारा कॉलम होना चाहिए, हमारी गिनती होनी चाहिए- नरेश राजवाड़े, प्रदर्शनकारी

प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जनगणना के सॉफ्टवेयर और प्रारूप में ओबीसी वर्ग के लिए भी अलग कॉलम निर्धारित किया जाए, ताकि सही आंकड़े सामने आ सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है, तो आने वाले समय में वे आंदोलन को और उग्र करते हुए दिल्ली में लोकसभा और प्रधानमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे।

वहीं, मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन प्राप्त किया और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। ओबीसी महासभा के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। रेलवे स्टेशन पर द्वितीय लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारी और जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा रेलवे की ओर से रेलवे पुलिस बल भी मुस्तैद रहा, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराया

एमसीबी। भीषण गर्मी के बीच जिले के नगर पंचायत खोंगापानी में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। नगर के अधिकांश वार्डों में पानी की किल्लत खुलकर सामने आ रही है, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में सप्ताह में एक बार तो कहीं 8 से 10 दिनों के अंतराल में पानी सप्लाई हो रही है। गर्मी के बढ़ते तापमान ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। दोपहर के समय जहां लोग तेज धूप से जूझ रहे हैं, वहीं पीने के पानी के लिए भी उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर किए गए निरीक्षण में सामने आया कि नगर पंचायत खोंगापानी के कई वार्डों में पेयजल की स्थिति बेहद खराब है। लोग पानी के लिए या तो लंबा इंतजार कर रहे हैं या फिर टैंकरों पर निर्भर हैं। कई परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी का जुगाड़ करने में ही पूरा दिन लग जाता है। वार्डवासियों का कहना है कि नियमित जल आपूर्ति नहीं हो रही है। कुछ इलाकों में 8 से 10 दिन में एक बार पानी मिल रहा है, जो पर्याप्त नहीं है।

रेलवे स्टेशन बिलासपुर में यात्रियों को गर्मी से राहत हेतु सराहनीय पहल

बिलासपुर। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं राहत के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 25 अप्रैल 2026 को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 2 एवं 3 पर यात्रियों को गर्मी से राहत प्रदान करने हेतु विशेष पहल की गई। वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों, वाणिज्य विभाग की स्पेशल टीम तथा स्काउट एवं गाइड के बच्चों द्वारा यात्रियों को शरबत एवं ठंडा पेयजल वितरित किया गया। इस दौरान यात्रियों ने इस पहल की विशेष सराहना की। यह सेवा कार्य वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार की मानवीय एवं जनसेवा आधारित पहल रेलवे की यात्री सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रेलवे प्रशासन द्वारा भविष्य में भी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बारनवापारा अभयारण्य में काले हिरणों 200 तक पहुंचे

भाटापारा। लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में फैला बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में उभरा है। एक समय ऐसा था जब यह अभयारण्य अपने प्रमुख वन्यजीव काले हिरण से लगभग खाली हो चुका था। लेकिन अब यही क्षेत्र करीब 200 काले हिरणों का सुरक्षित आवास बन गया है। छत्तीसगढ़ में इस उपलब्धि तक पहुंचने की प्रक्रिया लंबी और चुनौतीपूर्ण रही है। 1970 के दशक के बाद अतिक्रमण और प्राकृतिक आवास के नुकसान के कारण काले हिरण इस क्षेत्र से लगभग समाप्त हो गए थे और करीब पांच दशकों तक यहां स्थानीय रूप से विलुप्त रहे। अप्रैल 2018 में आयोजित राज्य वन्यजीव बोर्ड की नौवीं बैठक में पुनर्स्थापन योजना को स्वीकृति मिलने के बाद स्थिति में बदलाव आया। इसके बाद एक योजना के तहत काले हिरणों को फिर से बसाने की प्रक्रिया शुरू की। इसी प्रयास के परिणामस्वरूप उनकी संख्या बढ़कर लगभग 200 तक पहुंची। वन अधिकारियों के अनुसार, निमोनिया के कारण लगभग आठ काले हिरणों की मृत्यु हुई।

लाठी-डंडों से लैस नकाबपोशों ने परिवार पर किया हमला

बिलासपुर। शहर के सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा इलाके में आधी रात को हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। यहां 20 से अधिक नकाबपोश हमलावरों ने एक परिवार पर लाठी-डंडों से बर्बर हमला कर दिया, जिसमें महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रहीं। यह पूरी वारदात पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, यह हमला पुरानी रंजिश के चलते सुनियोजित तरीके से किया गया था। हमलावरों ने अचानक घर पर धावा बोलते हुए जमकर मारपीट की, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोशों की हिंसा साफ तौर पर देखी जा सकती है। बता दें कि घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही सरकंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है।

एक के बाद एक पुलिस ने गांजा के 17 पैकेट किए बरामद

गरियाबंद। गांजा आपने खेतों में उगाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी गांजा नहरों में बहते हुए देखा है? ऐसा ही नजारा मोहतरा से अतरमरा के बीच नहर में देखने को मिला, जहां गांजा से भरे पैकेट लोगों ने बहते हुए देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक-एक कर 17 गांजा से भरे पैकेट बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली कि नेशनल हाइवे 130 से 5 किमी दूरी पर स्थित पाण्डुका थाना क्षेत्र के फिंगेश्वर वितरक शाखा नहर में गांजा से भरा पैकेट बह रहा है। मौके पर पहुंची पाण्डुका पुलिस ने पैकेट को बरामद किया। पैकेट में करीबन 68 किलो से अधिक गांजा होने की संभावना जताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए है। जाहिर है कि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए गांजा तस्कर नहर में पैकेट फेंक गए थे। अब तस्करों तक पहुंचने के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है। नहर में गांजा से भरे पैकेट फेंके जाने की यह संभवत: पहली घटना है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं यह गांजा परिवहन का नया तरीका तो नहीं।

भरतपुर के कई गाँवों में खराब हैंडपंप हुए दुरुस्त

एमसीबी। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और गहराते जल संकट के बीच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कमर कस ली है। प्रशासन की सक्रियता से ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े हैंडपंपों को युद्ध स्तर पर सुधारा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। विभागीय टीम ने हाल ही में विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत घाघरा, बेला और लरकोडा का दौरा किया। यहाँ लंबे समय से खराब और बंद पड़े हैंडपंपों का न केवल निरीक्षण किया गया, बल्कि मौके पर ही उनकी मरम्मत कर उन्हें दोबारा चालू किया गया। भीषण गर्मी की तीव्रता को देखते हुए प्रशासन ने खराब हैंडपंपों को प्राथमिकता के आधार पर सुधारने के निर्देश दिए है। विभाग की इस मुस्तैदी से ग्रामीणों को अब स्वच्छ पेयजल के लिए दूर नहीं भटकना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस संवेदनशीलता और तत्परता की सराहना की है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जिले के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी हैंडपंप सुधार का कार्य निरंतर प्रगति पर है।

रेलवे बोर्ड द्वारा स्टेशन मास्टर पद का नाम अब अस्टेशन प्रबंधक

जगदलपुर। रेलवे प्रशासन में एक बड़ा बदलाव करते हुए बोर्ड ने स्टेशन मास्टर पद का नाम बदलकर अब स्टेशन प्रबंधक कर दिया है। इस निर्णय के बाद देशभर के रेलवे स्टेशनों पर तैनात स्टेशन मास्टरों को अब नए पदनाम से जाना जाएगा। यहां बस्तर संभाग के रेलवे स्टेशन में कार्यरत स्टेशन मास्टर बोर्ड के इस फैसल को लेकर खुशी जाहिर की है। मिली जानकारी के अनुसार जारी आदेश के बाद इस नए नियम को लागू किया गया है। इस आदेश के तहत स्टेशन मास्टर की पहचान अब स्टेशन प्रबंधक के रूप में होगी। यह बदलाव रेलवे की कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक और जिम्मेदारी आधारित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। बोर्ड का मानना है कि प्रबंधक शब्द न केवल स्टेशन मास्टर के कार्यप्रणाली का अधिक व्यापक भूमिका को दर्शाता है, बल्कि इससे स्टेशन संचालन में उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से परिभाषित करेगा।। जगदलपुर के डीआरएम ललित बोहरा ने बताया कि स्टेशन मास्टर का नाम बदलकर स्टेशन प्रबंधक किया गया।

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व एरिया में घुसकर पेड़ों की कटाई

- **आरोपियों ने टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण के उद्देश्य से लगभग 20 हेक्टेयर वनभूमि में फैले साल, इमारती और छोटे बड़े पेड़ों की कटाई कर दी.**

धमतरी-गरियाबंद। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत वन परिक्षेत्र सीतानदी में बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई और अतिक्रमण मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कोर क्षेत्र के परिसर नकबेल/घोटबेड़ा स्थित आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 322 एवं 323 में अवैध रूप से प्रवेश कर वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया गया। कुल 46 लोगों ने बिना अनुमति हथियारों के साथ कोर क्षेत्र में प्रवेश किया और अतिक्रमण के उद्देश्य से लगभग 20.608 हेक्टेयर वनभूमि में फैले साल, इमारती और मिश्रित प्रजाति के 86 से अधिक पेड़ों के साथ-साथ छोटे-बड़े हरे-भरे पौधों और छिंद घासों की कटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने वनभैंसा (छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु), बाघ, हाथी, तेंदुआ सहित अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और विचरण क्षेत्र को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया।

22 आरोपी गिरफ्तार

वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से माचिस, कुल्हाड़ी, चाकू, फावड़ा, हाजिरी पंजी, काटी गई लकड़ियां, साइकिल तथा खाने-पीने और रहने से संबंधित सामग्री बरामद की गई। सभी आरोपियों को 25 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर 26 अप्रैल 2026 को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नगरी के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के निर्देश पर गिरफ्तार 22 आरोपियों में से 5 महिला आरोपियों को महिला प्रकोष्ठ केंद्रीय कारागार रायपुर और 17 पुरुष आरोपियों को जिला जेल धमतरी भेजा गया है। स पूरे मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) क, ख, ङ, च, ज तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27, 29, 30, 31, 32, 51, 52 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है।

पहले भी कर चुके हैं अपराध, जमानत शर्तों का उल्लंघन

वन विभाग के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी वर्ष 2023 में 26 अप्रैल और 12 जून को अपराध दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद आरोपियों ने न्यायालय द्वारा निर्धारित जमानत शर्तों का उल्लंघन करते हुए तीसरी बार वन अपराध को अंजाम दिया। इस मामले में कुल 46 आरोपियों में से 25 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के भाई भूपेंद्र चंद्राकर के घर ईडी की दबिश

धमतरी। धमतरी जिले के कुरुद में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्रवर्तन निदेशालय यानी श्वष्ठ की टीम भारतमाला परियोजना जमीन घोटाले के जांच के सिलसिले में भूपेंद्र चंद्राकर के घर दबिश दी। पौ फटने से पहले कुरुद में भूपेंद्र चंद्राकर के घर पहुंची ईडी की टीम बीते सात घंटों से अपनी पड़ताल जारी रखे हुए हैं।

बताया जा रहा है कि टीम के सदस्य दस्तावेजों की पड़ताल करने के साथ-साथ उसके संबंध में पूछताछ भी कर रहे हैं। भूपेंद्र चंद्राकर के घर ईडी की दबिश की खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। लोगों में चर्चा होने लगी।

इस बीच स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। बहरहाल, ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सारे संकेत इशारा कर रहे हैं कि यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में की जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

विश्व रेडक्रॉस दिवस पर राज्य भर में होंगे विशेष कार्यक्रम राज्यपाल ने दिए निर्देश

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन ने कहा कि

रेडक्रॉस के मानव सेवा कार्यो का प्रचार-प्रसार जन-जन तक पहुंचाने के लिए सदस्यता अभियान को गति देना आवश्यक है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं विभिन्न वर्गों के गणमान्य नागरिकों को अभियान से जोड़ा जाए। श्री डेका ने 8 मई विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर राज्य एवं जिला शाखाओं में वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष श्री टोमन साहू ने मुलाकात की। इस दौरान रेडक्रॉस सोसायटी की गतिविधियों, सदस्यता अभियान तथा आगामी विश्व रेडक्रॉस दिवस के आयोजन के संबंध में राज्यपाल द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। श्री डेका ने 8 मई विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों को रेडक्रॉस स्टीकर लगाकर दान संग्रहण कार्यक्रम चलाएं। उन्होंने प्रदेश के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को जूनियर रेडक्रॉस और यूथ रेडक्रॉस से जोड़ने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से सेवा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में रेडक्रॉस सोसायटी के विभिन्न कार्यक्रमों और भविष्य की योजना पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर रेडक्रॉस सोसायटी के राज्यप्रतिनिधि श्री युवराज देशमुख और कोषाध्यक्ष श्री संजय पटेल उपस्थित थे।

डेका ने कारखानों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मजबूत करने के दिए निर्देश

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से सोमवार को

लोक भवन में छत्तीसगढ़ शासन के चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज श्री हिम शिखर गुप्ता ने मुलाकात की। भेंट के दौरान राज्यपाल श्री डेका ने कारखानों में होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने और श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि कारखानों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन हो, मशीनों की नियमित जांच की जाए तथा कर्मचारियों को समय-समय पर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग की जाए, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को समय रहते रोका जा सके और श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार हो।

राज्यपाल डेका ने स्वर्ण पदक विजेता आर्मरेसलर श्रीमंत झा को दी बधाई

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से सोमवार को लोकभवन में 64 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पैरा आर्मरेसलर श्री श्रीमंत झा ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने हाल ही में नार्वे के ईदफ्योर्ड में आयोजित हुए पैरा आर्मरेसलिंग कप 2026 प्रतियोगिता में 85 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत कर देश का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के निवासी श्रीमंत झा एक प्रसिद्ध भारतीय पैरा-आर्मरेसलर (विकलांग कुश्ती खिलाड़ी) हैं, जिन्होंने नॉर्वे पैरा-आर्म रेसलिंग कप 2026 में 85 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रौशन किया है। वे एशिया नंबर-1 और वर्ल्ड नंबर-3 के रूप में पहचान रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 64 से अधिक पदक जीत चुके हैं। श्री झा ने राज्यपाल को अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी। श्री डेका ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उनका सम्मान किया।

कोचली जलाशय योजना के लिए 19.39 करोड़ रुपये स्वीकृति

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा बलरामपुर जिले के विकासखण्ड-बलरामपुर की कोचली जलाशय योजना के कार्यों के लिए 19 करोड़ 39 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान किये गये हैं। योजना के प्रस्तावित कार्यों के उपरांत 350 हेक्टेयर में खरीफ एवं 150 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सहित कुल 500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से बदलेगा लखनपुर नगर पंचायत का स्वरूप

कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने 283 लाख के विकास परियोजनाओं का किया भूमिपूजन

रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि लखनपुर का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इन परियोजनाओं के माध्यम से नगर की आधारभूत संरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन कार्यों के पूर्ण होने से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति प्राप्त होगी। नगर पंचायत लखनपुर में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज 283 लाख रूपए की लागत से पूर्ण होने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का विधिवत भूमिपूजन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण से छत्तीसगढ़ के लखनपुर नगर पंचायत का स्वरूप तेजी से बदलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भूमिपूजन की गई परियोजनाओं में सड़क, नाली, सामुदायिक अधोसंरचना सहित विभिन्न आवश्यक विकास कार्य

शामिल हैं, जो न केवल नगर की मूलभूत जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि आने वाले समय में आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का आधार भी बनेंगे। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से लखनपुर का स्वरूप आधुनिक और सुव्यवस्थित नगर के रूप में उभरकर सामने आएगा।

मंत्री अग्रवाल ने नगर पंचायत लखनपुर के समस्त नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार जनहित के कार्यों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और भविष्य में भी विकास की यह गति लगातार जारी रहेगी। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से ही लखनपुर को यह महत्वपूर्ण सौगात प्राप्त हुई है। स्थानीय नागरिकों में विकास कार्यों को लेकर उत्साह का माहौल है और उन्होंने आशा जताई कि इसी तरह क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य होते रहेंगे। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर नगर निगम में महिला आरक्षण पर हंगामा

मेयर और बीजेपी पार्षद काले कपड़े पहनकर पहुंचे

रायपुर। नगर निगम की विशेष सामान्य सभा सोमवार को भारी राजनीतिक तनाव के बीच शुरू हुई। यह बैठक महिला सशक्तिकरण के लिए जनजागरूकता अभियान पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन शुरुआत से ही माहौल गरम हो गया। महापौर मीनल चौबे सहित भाजपा पार्षद काले कपड़े पहन कर पहुंचे और महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा शुरू होने से पहले भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस शर्म करो के नारे लगाए। भाजपा ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। बैठक के दौरान भी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर निंदा प्रस्ताव लाया गया। इस पर भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच

जोरदार नारेबाजी और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिला। सदन में स्थिति इतनी गरमा गई कि बार-बार हंगामे की स्थिति बनती रही। दोनों पक्ष एक-दूसरे को महिला विरोधी बताते रहे। इसके बावजूद बैठक की कार्यवाही जारी रखी गई। इधर विपक्ष ने शहर में बढ़ते जल संकट पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति ने कहा कि इस पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए चर्चा नहीं होगी। इससे विपक्ष और ज्यादा नाराज हो गया। वहीं भाजपा के पास दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत है, इसलिए निंदा प्रस्ताव के पास होने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है।

विशेष सत्र पर सियासत तेज : दीपक बैज का सरकार पर हमला, कहा-

राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए बुलाया गया सत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 30 अप्रैल को बुलाया गया विशेष सत्र राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और इसका मकसद कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना है।

दीपक बैज ने कहा कि राज्यपाल की अधिसूचना में महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख किया गया है, लेकिन महिला आरक्षण बिल 2023 पहले ही संसद से पारित होकर कानून बन चुका है। ऐसे में विधानसभा में इस पर चर्चा का क्या औचित्य है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह लोकसभा का अपमान नहीं है?

उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार को सत्र बुलाना ही है, तो ढाई साल के अपने कार्यों पर चर्चा करे और मोदी की गारंटी पर बहस कराए। बैज ने आरोप लगाया कि जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने के लिए यह विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लेकर भी क्ष्टष्ट चीफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जहां-जहां यह व्यवस्था लागू हुई है, वहां यह असफल साबित हुई है। राजधानी में कानून-व्यवस्था सुधारने के बजाय सिर्फ वसूली हो रही है। जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन जैसे मामलों में बेवजह चालान काटे जा रहे हैं, जबकि लूट, हत्या और चोरी जैसी गंभीर घटनाओं पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वसूली मास्टर बन गई है।

भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई कार्रवाई पर बैज ने कहा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसमें बड़े नेताओं की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलहाल केवल छोटे मोहरों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि बड़े जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईडी बड़े आरोपियों पर भी कार्रवाई करेगी?

वहीं वेदांता हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? यह दबाव के बाद दर्ज की गई। उन्होंने दावा किया कि आज भी यह एफआईआर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है और अब तक जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने इसे लीपापोती करार दिया। बीजेपी द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक आयोजित करने को लेकर भी बैज ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को पहले अपने कामों का हिसाब जनता को देना चाहिए। महतारी वंदन योजना, खाद की स्थिति और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता की राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिफिन लेकर पिकनिक मनाना जनता से संवाद नहीं है।

प्रकाश इण्डस्ट्रीज के इंडक्शन फर्नेस में रिसाव, बड़ा हादसा टला

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम हथनेवरा स्थित कारखाना मेसर्स-प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में शुक्रवार 24 अप्रैल को इंडक्शन फर्नेस से पिघली धातु के रिसाव की घटना सामने आई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई भी श्रमिक घायल नहीं हुआ, हालांकि हादसा गंभीर रूप ले सकता था।

जानकारी के अनुसार प्लांट में 15 टन क्षमता वाले इंडक्शन फर्नेस में रोज की तरह धातु पिघलाने का काम चल रहा था। इसी दौरान कल दोपहर करीब 2रू30 बजे फर्नेस की कॉइल में छेद हो गया, जिससे पानी का रिसाव शुरू हो गया। यह पानी गर्म पिघली धातु के संपर्क में आ गया। साथ ही फर्नेस की अंदरूनी लाइनिंग में भी छेद हो गया, जिससे पिघली धातु बाहर निकलने लगी और तेज आवाज हुई।

स्थिति को देखते हुए वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत फर्नेस की बिजली सप्लाई बंद कर दी और अंदर मौजूद धातु को ठंडा किया गया। उस समय कुल 6 कर्मचारी ड्यूटी पर थे, जिन्होंने सतर्कता दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया।

घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शुरुआती जांच में सुरक्षा से जुड़ी कुछ कमियां पाई गईं। इसके बाद संबंधित फर्नेस (ई-1) को फिलहाल बंद कर दिया गया है।

विभाग ने प्लांट प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और निर्देश दिया है कि सभी जरूरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के बाद ही फर्नेस को दोबारा चालू किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों के पालन की जरूरत को उजागर किया है।

राज्यपाल ने खैरागढ़ विवि की नई बस को दिखाई हरी झंडी

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने सोमवार को लोकभवन में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की नई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल छात्रों और स्टाफ के लिए परिवहन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस वाहन के माध्यम से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को कला, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए विभिन्न स्थानों तक आवागमन में सुविधा मिलेगी। इससे विद्यार्थियों को अपने प्रतिभा प्रदर्शन के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। यह कदम विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन और छात्रों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है। राज्यपाल श्री डेका ने वाहन के सदुपयोग, नियमित रखरखाव और विद्यार्थियों के हित में प्रभावी उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे संसाधन संस्थानों की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को नई गति देते हैं।

गर्मी में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने 15 जुलाई तक नलकूप खनन पर रहेगी रोक

रायपुर। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने रायपुर जिले में 15 जुलाई तक ग्रीष्म ऋतु के दौरान नये नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। कलेक्टोरेट से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। चालू गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले का 15 जुलाई तक जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। गर्मी के मौसम में लोगों को पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नये नलकूप खोदने पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।

जारी किए गए आदेश अनुसार रायपुर जिले में 15 जुलाई 2026 तक की अवधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। इस अवधि में पीने के पानी या पेयजल के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी नया नलकूप खनन नहीं होगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार के नये नलकूप खनन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। शासकीय-अर्द्धशासकीय एवं नगरीय निकायों को पीने के पानी के लिए अपने क्षेत्र अधिकार सीमा में आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन के अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

कलेक्टर डॉ सिंह ने नलकूप खनन की पूर्व अनुमति के लिए प्राधिकृत अधिकारी भी नियुक्त कर दिए है। प्राधिकृत अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग या नगरीय निकाय से रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में नये नलकूप खनन की अनुमति

दे सकेंगे। प्राधिकृत अधिकारी यह अनुमति छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही देंगे। रायपुर नगर निगम सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए नये नलकूप खनन की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी जाएगी। रायपुर राजस्व अनुभाग के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम रायपुर, आरंग राजस्व अनुभाग क्षेत्र के लिए एसडीएम आरंग, अभनपुर राजस्व अनुभाग के लिए एसडीएम अभनपुर और तिल्दा राजस्व अनुभाग के लिए एसडीएम तिल्दा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए है। नलकूप खनन या मरम्मत का काम पंजीकृत एजेंसी द्वारा किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा निर्देशों का उलंघन किए जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मनरेगा श्रमिकों की ई- के वाय सी में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल

रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिकों के ई-के वाय सी कार्य में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 97.11 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का ई-के वाय सी पूर्ण कर लिया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ ने केरलम, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों तथा कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को भी पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में छत्तीसगढ़ ने देश भर में अग्रणी स्थान हासिल किया है। प्रदेश में लगभग 58.16 लाख से ज्यादा मजदूरों की डिजिटल वेरिफिकेशन पूरी की गई हैए जो भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह डिजिटल प्रक्रिया फर्जी जॉब कार्डों को हटाने और सीधे वास्तविक लाभार्थियों के बैंक खातों में

मजदूरी पहुंचाने में मदद कर रही है।

यह उपलब्धि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल मार्गदर्शन एवं उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के सतत नेतृत्व, मॉनिटरिंग और प्रभावी रणनीति का परिणाम है। राज्य में योजनाबद्ध ढंग से अभियान चलाकर ई-के वाय सी की प्रक्रिया को तेज किया गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिकों को समयबद्ध रूप से इससे जोड़ा जा सका।

रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 58 लाख से अधिक सक्रिय श्रमिकों में से 56 लाख से अधिक का ई-के वाय सी सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीब और श्रमिक वर्ग के हितों के संरक्षण एवं उन्हें योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-के वाय सी के माध्यम से श्रमिकों को समय पर भुगतान एवं योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित हो रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम स्तर पर कार्यरत टीमों के समन्वित प्रयास का परिणाम है। उन्होंने बताया कि ई-के वाय सी से न केवल मस्टर रोल में फर्जी उपस्थिति पर रोक लगी है, बल्कि वास्तविक हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने में भी पारदर्शिता आई है। श्री शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई देते हुए निर्देशित किया कि शेष लंबित प्रकरणों को भी शीघ्र पूर्ण कर प्रदेश को 100 प्रतिशत ई - के वाय सी लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाए।

निंदा प्रस्ताव का किसी भी कानून पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं : अकबर

रायपुर। पूर्व केबीनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बयान जारी कर कहा है कि लोकसभा में 131 वां संविधान संशोधन विधेयक पारित न हो पाने के पश्चात् भाजपा लोगों को गुमराह करना चाह रही है। महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से 2023 को पारित हो चुका है तथा लोकसभा विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का कानून बन चुका है। महिला आरक्षण की आड़ में मनमाने परिसीमन करने भाजपा का षडयंत्र सफल नहीं हुआ तो वह गैर भाजपा पर्टियों पर महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने देने का झूठा आरोप लगा रही है जबकि महिला आरक्षण

विधेयक वर्ष 2023 में ही पारित हो चुका है। प्रदेश के पूर्व केबीनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्ति राज्यपाल के पास है लेकिन व्यवहार में यह निर्णय मंत्री परिषद (केबिनेट) की सलाह पर होता है। यदि सरकार चाहे तो किसी विशेष मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश कर सकती है। सामान्यत: विशेष सत्र राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दो पर चर्चा के लिए, विश्वास मत/बहुमत परीक्षण, बजट या अनुपूरक बजट पारित करने के लिए, प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था संकट या विशेष कानून पारित करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन मामला अत्यंत गंभीर हो, तात्कालिक या राजनैतिक रूप से महत्वपूर्ण हो तो सरकार विशेष सत्र बुला सकती है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि विधानसभा इसलिए है ताकि राज्य अपनी जनता के लिए अपने स्तर पर शासन चला सके और स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकें। सामान्यत: निंदा प्रस्ताव नियमित सत्र में लाया जाता है और आमतौर पर विपक्ष द्वारा सरकार की नीतियों या कार्यों की आलोचना के लिए लाया जाता है।

छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार भाजपा सरकार विधानसभा का विषेश सत्र निंदा प्रस्ताव के लिए बुला रही है। विधानसभा द्वारा पारित ऐसा कोई भी निंदा प्रस्ताव प्रतीकात्मक होता है। इसका कोई भी कानून पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये एक राजनैतिक संदेश देने की कोशिश है। अब छत्तीसगढ़ में जिनको भाजपा की सरकार संदेश देना चाहती है उन तक ये संदेश पहुंचेगा या नहीं, यह समय बताएगा।

29 या 30 अप्रैल को जारी हो सकते हैं 10वीं-12वीं के नतीजे

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल लाखों विद्यार्थियों का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 29 या 30 अप्रैल को जारी किए जा सकते हैं। मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। फिलहाल काउंटिंग मिलान और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में बोर्ड किसी भी समय परिणाम जारी करने की घोषणा कर सकता है। बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं 20 और 21 फरवरी से शुरू हुई थीं, जो 18 मार्च तक चलीं। हालांकि इस दौरान हिंदी पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद 10 अप्रैल को दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी थी, जिसके कारण रिजल्ट में देरी हुई। पहले बोर्ड ने 15 अप्रैल तक परिणाम जारी करने की योजना बनाई थी। इस वर्ष हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) परीक्षा में कुल 3,20,535 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जबकि हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) में 2,45,785 छात्रों ने परीक्षा दी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

भारतीय राजनीति के बदलते समीकरण

सनत जैन

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसदों के इस्तीफे और उनके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने से लोटस अभियान को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। विशेष रूप से पंजाब, जहां आप की सरकार है, पंजाब की राजनीति के लिये यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। पंजाब में भाजपा लंबे समय से अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर भाजपा 5 दशक से अपना झंडा गाड़ना चाहती थी, लेकिन वह आज तक सफल नहीं हो पाई। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आप आदमी पार्टी की पैठ हैं। कांग्रेस में पिछले दशक में काफी तोड़-फोड़ हुई है। अब आप नेताओं में दल-बदल शुरू हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का इस्तीफा इस बात का संकेत है। आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में बड़े राजनीतिक बदलाव होने जा रहे हैं। पंजाब सरकार इस संकट में गिर भी सकती है। अरविन्द केजरीवाल की नजर पंजाब के बाद गुजरात पर बनी हुई है। अगले वर्ष पंजाब और गुजरात में चुनाव होना है। गुजरात में केजरीवाल सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे हैं। भाजपा इसे चुनौती मानकर आम आदमी पार्टी को पंजाब में उलझाकर गुजरात में केजरीवाल और आप को रोकना चाहती है। वहीं पंजाब में भाजपा कब्जा करना चाहती है। ताकि वह अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के विस्तार को रोक सके। भाजपा ने यह राजनीतिक सक्रियता ऐसे समय में बढ़ाई है, जब बंगाल और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया जारी है। उनके परिणाम जल्द आने वाले हैं। भाजपा ने नारी वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के नाम पर महिलाओं को लुभाने की राजनीति शुरू कर दी है। प. बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसे मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर प्रचारित किया है। पंजाब भी उसी क्रम में शामिल है। भाजपा महिलाओं को आगे करके आक्रामक राजनीति शुरू कर दी है। ऐसे समय पर लोटस अभियान को संचालित करना अगली चुनावी रणनीति का हिस्सा है। विश्लेषकों का मानना है, सांसदों के इस्तीफे और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को जोड़कर भाजपा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव एवं 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट गई है। विपक्षी दलों और इंडिया अलायंस में शामिल विपक्षी दलों के बढ़ते आक्रामक रुख के बीच भाजपा अपने प्रभुत्व को बनाए रखने, विपक्षी दलों में फूट डालने के लिए हर संभव रणनीति को अपना रही है। साल 2027 में सात राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी अभी से संगठनात्मक और राजनीतिक स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने लोटस अभियान एवं जांच एजेंसियों के माध्यम से खुद को उन राज्यों में मजबूत करना चाहती है, जहां उसका प्रभाव ना के बराबर है। एक बड़ा प्रश्न है कि क्या इस तरह की रणनीतियां लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की निष्पक्षता और राजनीति में विपरीत असर नहीं डालती हैं? विपक्ष आरोप लगाता रहा है, संवैधानिक संस्थाएं सरकार के प्रभाव में काम कर रही हैं। भाजपा इन आरोपों को खारिज करती है। लोटस अभियान के कारण भाजपा की साख में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भारत की राजनीति में लोटस अभियान अब लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन चुकी है। पिछले 12 वर्षों में जितने भी दल बदल हुए हैं, उसमें दल-बदल करने वाले सभी राजनैतिक दलों के नेता भाजपा में गए हैं। लोटस अभियान की तहत से कई सरकारें गिराई गई हैं।

सवालों का सामना करेगी आम आदमी पार्टी?

उमेश चतुर्वेदी

राजनीति सपने दिखाते हुए लोगों से उन्हें पूरा करने के वायदे करती है, लेकिन लोगों को उन्हीं राजनीतिक दलों के दिखाए सपनों पर भरोसा होता है, जिनकी साख होती है। लोकतंत्र में साख हासिल करने का सबसे बड़ा और जांचा-परखा हथियार आंदोलन ही है। कई बार जनाकांक्षाओं के उफान में आंदोलन से उभरी राजनीति को सफलताएं मिल भी जाती हैं, लेकिन वे लंबे समय तक टिक नहीं पातीं। उनमें बिखराव शुरू हो जाता है। आम आदमी पार्टी के साथ भी क्या ऐसा ही हो रहा है? राघव चड्ढा की अगुआई में आप के दस में से सात सांसदों के बगावती होने और बीजेपी में शामिल होने के बाद कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं।

इतने सांसदों के एक साथ पार्टी छोड़ने से आप की बौखलाहट स्वाभाविक है। पार्टी की ओर से राघव चड्ढा और उनके साथियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में पाला बदल लिया है। इस आरोप के बाद पहला सवाल तो आम आदमी पार्टी पर ही उठता है। ईडी या सीबीआई का डर तो उसे ही होगा, जो भ्रष्टाचारी हो। चूंकि आम आदमी पार्टी का उभार देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से हुआ था, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन देने का उसका वादा भी रहा। ऐसे में अगर उसके सांसद भ्रष्टाचार के डर से पाला बदलते हैं तो इसका मतलब तो यही निकलेगा कि भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली पार्टी में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका सांसद भ्रष्टाचार में कैसे शामिल हो सकता है? अगर शामिल भी हुआ तो उसके नेतृत्व ने इसकी रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम क्यों नहीं उठाया। सवाल यह भी उठता है कि क्या भ्रष्टाचार रोकने वाली पार्टी भी दूसरी पार्टियों जैसी क्यों बन गई?

इंदिरा सरकार की जन विरोधी नीतियों और कांग्रेसी सरकारों में भ्रष्टाचार के खिलाफ 1970 के दशक में जेपी आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में शामिल हो रहे लोगों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जयप्रकाशन नारायण को एक पत्र लिखा था। जेपी आंदोलन का एक लक्ष्य व्यवस्था को बदलना भी था। चंद्रशेखर ने अपने पत्र में आशंका जताई थी कि आंदोलन में शामिल होने वाले नेता व्यवस्था में बदलाव के लिए नहीं,

सत्ता के लिए आ रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा था कि सत्ता में आने के बाद ये ही नेता व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे और भविष्य में अपनी-अपनी जातियों के नेता बन जाएंगे। उन नेताओं की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि चंद्रशेखर की आशंका सच हुई। उस आंदोलन से निकलने नेताओं में से ज्यादातर पारिवारिक पार्टियों के नेता हैं और ज्यादातर पर भ्रष्टाचार को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। जेपी आंदोलन में उभरे नेताओं का जातीय आधार पर टिकी राजनीति के चलते अस्तित्व बचा हुआ है, लेकिन असम से घुसपैठियों को बाहर निकालने वाले आंदोलन से उभरी पार्टी असम गणपरिषद के नेताओं के बारे में आज देश कितना जानता है? जबकि केजरीवाल की तरह उसके नेताओं ने छात्रावास से निकल कर सीधे सत्ता के गलियारों पर कब्जा कर लिया था।

यह पहला मौका नहीं है कि अन्ना आंदोलन से उभरी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से बड़े नाम निकले हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में शामिल रहे योगेंद्र यादव और मशहूर वकील प्रशांत भूषण को पार्टी ने शुरू में ही या तो निकाल दिया था या वे निकल गए थे। प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने आम आदमी पार्टी की स्थापना के लिए भारी रकम दी थी। अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के साथ कंधा से कंधा भिड़ाकर खड़ी रहीं पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी को भी जल्द ही पार्टी से अलग राह चुननी पड़ी थी। पार्टी का शुरू के दिनों से ही बड़ा चेहरा रहीं शाजिया इल्मी भी वहां की बजाय अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे आनंद कुमार हों या फिर कैलाश गहलोत, सबको केजरीवाल की अगुआई वाली पार्टी से अलग राह चुननी पड़ी है।

जब भी किसी दल से कोई नेता बगावत करके नई राह चुनता है, तब वह दल विशेष उसे गद्दार कहता है। राघव चड्ढा की अगुआई में केजरीवाल के खिलाफ बगावत करके नई राह चुनने वाले सांसदों को भी गद्दार कहा जाना कोई नई बात नहीं है। वैसे अपने निजी अहम् या अनदेखी के चलते दलों को छोड़ना या फायदे के लिए दल बदलना भारतीय राजनीति में जाना-पहचाना है। इस लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी से बगावत होना भी नया नहीं कहा जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस पार्टी की डेढ़ दशक की उम्र भी नहीं हुई, उसके महत्वपूर्ण नेता आखिर क्यों उसे छोड़कर निकल रहे हैं? यह सवाल और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, क्योंकि इस बार पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में से राघव चड्ढा और संदीप पाठक तो पार्टी के शुरूआती दिनों से रणनीतिकार और संगठक रहे हैं। दोनों केजरीवाल के नजदीक भी माने जाते रहे। दिल्ली से राज्यसभा सांसद बनने से पहले स्वाति मालीवाल भी केजरीवाल की करीबी मानी जाती रहीं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के एजेंडे को ही आगे बढ़ाया। उनका कार्यक्षेत्र दिल्ली ही था, लेकिन मणिपुर और दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के कथित महिला अत्याचारों की जांच करने वह इसीलिए पहुंचती रहीं, ताकि बीजेपी को अपने दलीय एजेंडे के तहत कठघरे में खड़ा किया जाए। मुख्यमंत्री निवास में उनसे हुई कथित मारपीट के बाद से वे बगावती हैं। राघव चड्ढा के साथ जाकर उन्होंने अपनी बगावत को सियासी वैधता देने की कोशिश की है।

आप में इस बड़ी बगावत का सीधा फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को ही होगा। अगले साल गुजरात और पंजाब में चुनाव हैं। गुजरात में आप बार-बार तीसरा कोण बनाने की कोशिश करती है। बगावत से उसके जमीनी कार्यकर्ताओं पर असर पड़ेगा और तीसरा कोण बनाने में वह शायद ही सफल हो पाए। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब पर निगाह है। वहां वह अब तक कायदे से उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा पाई है। याद करना चाहिए कि राघव लंबे समय तक पंजाब के प्रभारी रहे हैं। आप ने पिछला विधानसभा चुनाव भी उनके ही प्रभार में जीता था। बीजेपी इन नेताओं के जरिए पंजाब में आप के किले में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। वैसे भी चड्ढा के साथ गए नेताओं में सबसे ज्यादा पंजाब से ही चुनकर आए हैं। वैसे इस बगावत से पंजाब की राजनीति में कांग्रेस की राह भी आसान हो सकती है। उसके छिटके हुए कार्यकर्ता भी उसकी ओर लौटना शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने के चलते स्थानीय स्तर पर कांग्रेसी नेताओं के लिए आप सरकार का कड़ा विरोध कर पाना आसान नहीं था। संसदीय दल में बगावत के चलते उनका भी मनोबल बढ़ सकता है।

वैसे इन नेताओं की संसद सदस्यता खत्म कराने को लेकर भी राजनीतिक दांवपेच शुरू हो गए हैं। कपिल सिब्बल ने तो तर्क ही दे दिया है कि किसी पार्टी में शामिल होने के लिए टूटे हुए गुट को पहले दल बनाना होता है। राघव की अगुआई वाले नेताओं ने यह कदम ना उठाते हुए सीधे अलग होकर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इस तर्क के जरिए राज्यसभा सभापति को आम आदमी पार्टी चिट्ठी भी देने जा रही है। सिब्बल के दिए तर्क को लेकर बीजेपी ने सोचा नहीं होगा, ऐसा मानना बेवकूफी होगी। जाहिर है कि बीजेपी ने भी सोचकर पत्ते खेले हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अगर वहां के आप विधायकों में भी बड़ी टूट-फूट हो तो हैरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बागी नेताओं की अगुआई में ऐसी कोशिशें होना स्वाभाविक है।

आम आदमी पार्टी में अब तक छोटी बगावतें होती रही हैं। लेकिन यह पहला मौका है, जब संसदीय दल का बड़ा हिस्सा अलग हो चुका है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व को अपने गिरेबान में झांकना होगा। उसे विचार करना होगा कि आखिर उसके किले में कहां सुराख है और वह किस वजह से बड़ी हो रही है। राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता ऐसी गोंद होती है, जिससे दलीय कार्यकर्ता चिपके रहते हैं। आप के पास पंजाब की सत्ता है, फिर भी अगर बड़ी बगावत होती है, तो निश्चित तौर पर उसके पीछे गहरी नाराजगी और उसके कारण होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप का नेतृत्व इस दिशा में सोचना शुरू करेगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

वहाँ वेद (ग) में इन्द्र के मुख से अनेक व्यक्तियों के मार डालने की आत्मप्रशंसा प्रकट करवा कर अन्त में अन्यान्य वेदातु-यायियों को भी इन्द्र की तरह वैसा आचरण करने के लिये उकसाया गया है एवं स्पष्ट शब्दों में चोरी, भ्रूण हत्या और मातृ-पितृ-वध जैसे घोरतम पाप के कर डालने पर भी लोम च नामीयत कहाते हुये अपने रोम संभवतः लोक प्रसिद्ध अश्लील महावरे के अनुसार गुह्य स्थानस्थ केश] के न उखड़ सकने को शेखी भंगारी गई है। ऐसी दशा में विज्ञ पाठक स्वयं सोच सकते हैं कि उक्त आख्यान के केवल पौराणिक-स्वरूप पर आक्षेप करने वाले महाशय कितने अन्धेरे में हैं। यद्यपि इस आख्यान के समाधान का उत्तरदायित्व हम से अधिक वैदिकता का मिथ्या दम भरने वाले शङ्कावादी महाशयों पर ही है तथापि अन्यान्य विधाम्मयों की जिज्ञासा पूर्ण करने के लिये इस पर भी दो शब्द लिखना अनावश्यक न होगा।

वास्तव में इस आख्यान में वर्षाकारक वायु की वैज्ञानिक उत्पत्ति का उल्लेख किया है, तद्यथा- जिसके खण्ड (टुकड़े टुकड़े) न किये जा सकें एवंभूत अन्तरिक्ष कक्षा ही अदिति है, उससे उत्पन्न होने वाले अन्तरिक्षस्थानीय वायु को ही इन्द्र कहते हैं। स्थूल परमाणुपुञ्जमय होने के कारण, खण्डन की जा सकने लायक पृथ्वी को ही दिति कहते हैं। सृष्टि के उत्पत्तिकाल में यह पृथ्वी जाज्वल्यमान अग्निपिण्ड के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं थी, उस समय इस पर अत्युग्र उष्णता के कारण किसी भी प्राणी का जीवित रह सकना सर्वथा असम्भव था, परन्तु पृथ्वी की वह उष्णता जब धीरे धीरे शांत होने लगी, तब कभी एक मुहूत के बाद पृथ्वी प्राणियों के रहने लायक बन सकी। श्री वेदव्यास जी नै पृथ्वी के इस परिवर्तन को पुंसवन-व्रत के नाम से याद किया है। अर्थात- पुं = पुरुषों [उपलक्षण से प्राणिमात्र] के सवन प्रसव किम्वा उत्पत्ति को ही पुंसवन कहते हैं। **क्रमशः ..**

विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस

सुनील कुमार महला

प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) द्वारा विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वास्तव में, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर काम करने वालों की उचित सुरक्षा, उनके बेहतर स्वास्थ्य तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि सुरक्षित कार्यस्थल केवल कर्मचारियों का अधिकार ही नहीं, बल्कि उत्पादकता(प्रोडेक्टीविटी) बढ़ाने और समाज तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए भी अनिवार्य है। सच तो यह है कि कोई भी काम किसी व्यक्ति की जान या उसके स्वास्थ्य से बड़ा नहीं हो सकता। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।हमारे यहां कहा भी गया है कि-पहला सुख निरोगी काया। दुनिया की तमाम धन-दौलत, ऊंचे पद और सुख-सुविधाएं, विलासिता सबकुछ व्यर्थ हैं, यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ न हो। हमें यह याद

रखना चाहिए कि स्वस्थ मस्तिष्क ही हमारी रचनात्मक सोच का आधार है और मस्तिष्क व शरीर स्वस्थ होगा तभी कोई मनुष्य कठिन परिश्रम कर सकता है।सच तो यह है कि जब हम स्वस्थ और सुरक्षित होते हैं, तब अधिक रचनात्मक, अधिक उत्पादक बनते हैं और जीवन में सफलता का आधार तैयार करते हैं। स्वस्थ रहकर हम न केवल अपने जीवन का असली आनंद लेते हैं, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुरक्षित व सही रख सकते हैं। अक्सर यह कहा जाता कि एक बीमार राजा की तुलना में एक स्वस्थ भिखारी अधिक सुखी और शक्तिशाली होता है।

हाल फिलहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन विश्वभर में विभिन्न श्रमिकों के अधिकारों तथा सुरक्षित कार्यस्थलों के लिए कार्य करता है।पाठक जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में हर वर्ष लाखों लोग कार्यस्थल दुर्घटनाओं या काम से जुड़ी अनेक बीमारियों व रोगों का शिकार होते हैं।विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवसको मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल दुर्घटनाओं को रोकना, व्यावसायिक रोगों से बचाव करना, कर्मचारियों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा एक सुरक्षित, सुंदर व अच्छी कार्य संस्कृति विकसित करना है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि व्यावसायिक रोग वे रोग या बीमारियाँ हैं, जो किसी व्यक्ति को उसके काम, कार्यस्थल या पेशे की परिस्थितियों के कारण हो जाती हैं। अर्थात नौकरी या व्यवसाय से जुड़े वातावरण, रसायनों, धूल, शोर, तनाव, मशीनों या संक्रमण के कारण होने वाले रोग व्यावसायिक रोग कहलाते हैं।

आज बहुत से लोग ऐसे कल-कारखानों में काम करते हैं, जहां उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। उदाहरण के तौर पर पटाखों के कारखानों में जलने की दुर्घटनाएं, बारूद की गंध, धुएँ से आंखों व त्वचा के गंभीर और खतरनाक रोग तथा विस्फोट से चोट लगने की घटनाएं होती हैं। बीड़ी बनाने के उद्योगों में खांसी, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, त्वचा एलर्जी तथा निकोटीन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं।

भारत-दक्षिण कोरिया रिलेशन्स आज के दौर में

डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध आज के वैश्विक दौर में नई अहमियत प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और क्षेत्रीय शांति के समर्थक हैं। एशिया के बदलते शक्ति संतुलन, चीन की बढ़ती आक्रामकता, आपूर्ति श्रृंखला संकट, यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व तनाव और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत तथा दक्षिण कोरिया को एक-दूसरे के और करीब आने का अवसर दिया है। दोनों देशों के बीच वर्षों से मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन अब समय की मांग है कि इन्हें नई ऊर्जा, नई दिशा और व्यावहारिक सहयोग के साथ आगे बढ़ाया जाए।

भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध केवल आधुनिक कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार भी मजबूत हैं। प्राचीन समय से दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संपर्क की चर्चा मिलती है। कोरिया में अयोध्या की राजकुमारी सुरिरत्ना, जिन्हें वहां रानी ह्यो ह्वांग-ओक के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख दोनों देशों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है। यह संबंध आज भी लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव का आधार है। इसी कारण दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और जनसंपर्क की संभावनाएँ बहुत अधिक हैं।

राजनयिक स्तर पर भारत और दक्षिण कोरिया ने वर्ष 1973 में औपचारिक संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में लगातार प्रगति हुई है। वर्ष 2010 में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया और बाद में इसे विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों देश एक-दूसरे को दीर्घकालिक सहयोगी के रूप में देखते हैं। उच्च स्तरीय यात्राएँ, विदेश मंत्री स्तर की बैठकें, व्यापारिक संवाद और रक्षा वार्ताएँ इन संबंधों को लगातार मजबूत कर रही हैं।

आर्थिक क्षेत्र में दक्षिण कोरिया भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है। दक्षिण कोरिया तकनीकी

रूप से उन्नत, औद्योगिक रूप से मजबूत और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जबकि भारत विशाल बाजार, युवा जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं। द्विपक्षीय व्यापार हाल के वर्षों में बढ़ा है और लगभग 27 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। हालांकि यह क्षमता की तुलना में अभी भी कम है। भारत का दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार घाटा भी चिंता का विषय बना हुआ है।

दक्षिण कोरिया की प्रमुख कंपनियाँ भारत में लंबे समय से निवेश कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मोबाइल निर्माण, स्टील, शिपबिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कोरियाई कंपनियों की मजबूत उपस्थिति है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया का निवेश अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ग्रीन एनर्जी जैसे अभियानों में कोरियाई तकनीक तथा पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इसके बावजूद कुछ चुनौतियाँ भी हैं। वर्ष 2010 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी ष्टश्वक्र लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य व्यापार को गति देना था। लेकिन अपेक्षित परिणाम पूरी तरह सामने नहीं आए। गैर-टैरिफ बाधाएँ, गुणवत्ता मानकों से जुड़े नियम, जटिल नियामक प्रक्रियाएँ, लॉजिस्टिक समस्याएँ और बाजार पहुँच की कठिनाइयाँ व्यापार वृद्धि में रुकावट बनती रही हैं। भारत को अपने निर्यात में विविधता लानी होगी, जबकि दक्षिण कोरिया को भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने होंगे।

आज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़े बदलाव हो रहे हैं। कंपनियाँ केवल चीन पर निर्भरता कम करना चाहती हैं और नए उत्पादन केंद्र खोज रही हैं। यह स्थिति भारत और दक्षिण कोरिया दोनों के लिए अवसर लेकर आई है। दक्षिण कोरियाई कंपनियाँ यदि भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन केंद्र स्थापित करती हैं, तो उन्हें विशाल बाजार, सस्ती श्रमशक्ति और रणनीतिक स्थिति का लाभ मिलेगा। वहीं भारत को तकनीक, रोजगार और निर्यात क्षमता में वृद्धि प्राप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, बैटरी निर्माण, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन और जहाज निर्माण ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सहयोग तेजी से बढ़ सकता है।

रणनीतिक दृष्टि से भी दोनों देशों का सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, खुला और समावेशी व्यवस्था का समर्थन करता है। दक्षिण कोरिया भी क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा का समर्थक है। चीन की आक्रामक नीतियाँ, समुद्री मार्गों पर दबाव और क्षेत्रीय तनाव ने कई देशों को नए साझेदार खोजने पर मजबूर किया है। भारत और दक्षिण कोरिया इस संदर्भ में स्वाभाविक सहयोगी बन सकते हैं।

हालाँकि दक्षिण कोरिया की सुरक्षा प्राथमिकताएँ कुछ अलग हैं। उसका प्रमुख ध्यान उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे और अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन पर केंद्रित रहता है। दूसरी ओर भारत की चिंताएँ चीन, हिंद महासागर, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ी हैं। फिर भी दोनों देशों के हित कई क्षेत्रों में समान हैं। रक्षा उद्योग सहयोग, साइबर सुरक्षा, समुद्री निगरानी, आतंकवाद विरोधी प्रयास और नई सैन्य तकनीकों में संयुक्त कार्य किया जा सकता है।

रक्षा क्षेत्र में दक्षिण कोरिया ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। उसके पास आधुनिक रक्षा उत्पादन क्षमता है। भारत यदि संयुक्त उत्पादन, तकनीकी हस्तांतरण और अनुसंधान सहयोग पर जोर दे, तो दोनों देशों को लाभ हो सकता है। भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति और दक्षिण कोरिया की तकनीकी क्षमता मिलकर नई संभावनाएँ पैदा कर सकती हैं।

तकनीक आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार बन चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5त्न, 6त्न, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल नवाचार भविष्य की अर्थव्यवस्था तय करेंगे। दक्षिण कोरिया इन क्षेत्रों में अग्रणी देशों में शामिल है, जबकि भारत डिजिटल प्रतिभा, सॉफ्टवेयर क्षमता और स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि दोनों देश डिजिटल ब्रिज बनाकर साथ काम करें, तो एशिया में तकनीकी नेतृत्व का नया मॉडल सामने आ सकता है।

शिक्षा और मानव संसाधन सहयोग भी संबंधों को मजबूत कर सकता है। भारतीय छात्र दक्षिण कोरिया में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कोरियाई छात्र भारत की संस्कृति, इतिहास, योग, आयुर्वेद, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं। विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी, छात्रवृत्तियाँ और संयुक्त शोध कार्यक्रम भविष्य में मजबूत आधार बन सकते हैं।

सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारत में कोरियाई संगीत, फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की लोकप्रियता बढ़ी है। वहीं दक्षिण कोरिया में भारतीय योग, भोजन, नृत्य और आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति रुचि देखी जा रही है। यह सांस्कृतिक जुड़ाव केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि लोगों के बीच विश्वास और समझ को बढ़ाने का माध्यम है। पर्यटन, सांस्कृतिक उत्सव, भाषा शिक्षा और मीडिया सहयोग से यह रिश्ता और गहरा हो सकता है।

आज का इतिहास

1847 जार्ज बी. वेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यायालय में जाने वाले पहले अश्वेत नागरिक बने।
1851 सांता क्लारा कॉलेज सांता क्लारा, कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया।
1855 यूएस में पहला पशु चिकित्सा कॉलेज बोस्टन में शामिल किया गया।
1883 स्कॉटलैंड के मेलरोसे आरएफसी में पहला सात टूर्नामेंट खेला गया।
1910 इंग्लैंड में क्लोड ग्राहम व्हाइट नाम के पायलट ने पहली बार रात में विमान उड़ाया।
1910 फ्रांसीसी मैन लुइस पॉलहन ने इंग्लैंड में पहली लंबी दूरी की हवाई जहाज की दौड़ में लंदन से मैनचेस्टर की हवाई दौड़ जीती।
1914 अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया के एस्सेल्स इलाके में एक कोयला खदान हादसे में 181 लोगों की मौत।
1923 लंदन का वेम्बली स्टेडियम, जिसे तब एम्पायर स्टेडियम के रूप में जाना जाता था, पहली बार जनता के लिए बंद कर दिया गया था और 1923 एफए कप फाइनलबेटन बोल्टन वांडरर्स और वेस्ट हैम यूनाइटेड फुटबॉल क्लबों का आयोजन किया।
1932 इंसानों के लिए पीत ज्वर का टीका विकसित करने की घोषणा की गई।
1935 रूस की राजधानी मॉस्को में भूमिगत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई।
1944 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, व्यायाम टाइगर, नॉर्मंडी के आक्रमण के लिए बड़े पैमाने पर पूर्वाभ्यास, जर्मन एस-बोट्स ने मित्र देशों के काफिले पर हमला किया, जिसमें 946 अमेरिकी सैनिक मारे गए।
1949 फिलीपींस की पूर्व प्रथम महिला अरोरा क्यूज़ोन, उनके पोते, और दस बायस्टैंडरों की हत्या फिलीपीन कम्युनिस्ट पार्टी के सैन्य दल ने की थी।
1965 डोमिनिकन गृह युद्ध शुरू होने के चार दिन बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश पर आक्रमण किया, जिसका लक्ष्य लिंडन जॉनसन ने संभावित दूसरी क्यूबाई क्रांति के रूप में देखा।
1975 दक्षिण वियतनामी सेना के प्रमुख काओ वान विओक, साइगॉन में उत्तरी वियतनामी बंद होने के कारण भाग गए।
1993 कार्लो चैंपियन पूर्व कम्युनिस्टों के साथ इतालवी सरकार बनाती है।
1994 पूर्व सीआईए प्रतिवाद अधिकारी और विश्लेषक एल्ड्रिच एम्सलेड ने सोवियत संघ और बाद में रूस को अमेरिकी रहस्य बताने के लिए दोषी ठहराया।

पश्चिम बंगाल चुनाव में साइलेंट वोटर के प्रभाव की चर्चा

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही तीव्र भावनाओं,जटिल सामाजिक समीकरणों और उच्च स्तर की जनभागीदारी के लिए जानी जाती रही है,लेकिन 23 अप्रैल 2026 को हुए मतदान और 24 अप्रैल 2026 को सामने आए पहले चरण के मतदान के आंकड़ों ने इस परंपरा को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। लगभग 93 प्रतिशत औसत मतदान और कई विधानसभा क्षेत्रों में 98 प्रतिशत से अधिक मतदान केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक ऊर्जा,राजनीतिक ध्रुवीकरण और मतदाताओं की असाधारण सक्रियता का संकेतक है।इस अभूतपूर्व मतदान ने न केवल राज्य के भीतर राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया है,बल्कि राष्ट्रीय स्तरपर भी चुनावी विश्लेषकों, राजनीतिक दलों और नीति निर्माताओं के बीच गहन चर्चा को जन्म दिया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुख़दास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि सबसे पहले इस रिकॉर्ड मतदान के स्वरूप को समझना आवश्यक है।2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 83.2 प्रतिशत मतदान हुआ था,जिसे उस समय भी उच्च माना गया था। इसके मुकाबले 2026 में करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि केवल प्राकृतिक उतार-चढ़ाव नहीं मानी जा सकती।यह वृद्धि संकेत देती है कि इसबार क़ा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता बनाए रखने का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह मतदाताओं के लिए पहचान,सुरक्षा विकास और राजनीतिक भविष्य से जुड़ा व्यापक जनमत संग्रह बन चुका है। जब मतदान प्रतिशत 90 के पार जाता है, तो आमतौर पर यह माना जाता है कि समाज के वे वर्ग भी मतदान में शामिल हुए हैं, जो सामान्यत: निष्क्रिय रहते हैं।

साथियों बात अगर हम इस बढ़ी हुई भागीदारी के पीछे कई कारक काम कर रहे हैं इसको समझने की करें तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक ध्रुवीकरण। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से वैचारिक और सामाजिक विभाजन तीखा हुआ है, उसने मतदाताओं को निष्क्रिय रहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। दूसरा कारक है महिला मतदाताओं की अभूतपूर्व भागीदारी। रिपोर्ट्स के अनुसार कई क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा,जो यह संकेत देता है कि कल्याणकारी योजनाएं, सुरक्षा का मुद्दा और सामाजिक सम्मान जैसे विषय निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है प्रशासनिक सख्ती और सुरक्षा व्यवस्था,जिसे इलेक्शन कमिशन ऑफ़ इंडिया ने लागू किया। केंद्रीय बलों की तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और बूथ स्तर पर पारदर्शिता ने मतदाताओं में विश्वास बढ़ाया।अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस बंपर मतदान का राजनीतिक लाभ किसे

मिल सकता है। पारंपरिक चुनावी विश्लेषण कहता है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है, तो यह अक्सर सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इन्कम्बेंसी) का संकेत होता है। इसका कारण यह है कि असंतुष्ट मतदाता अधिक संख्या में मतदान के लिए बाहर निकलते हैं। यदि इस सिद्धांत को लागू किया जाए, तो विपक्षी दलों को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य इतना सरल नहीं है। यहां सत्तारूढ़ दल की जमीनी पकड़, संगठनात्मक ताकत और लाभार्थी योजनाओं का प्रभाव भी सटीक रूप से अत्यंत गहरा है।

साथियों बात अगर हम इसको उदाहरण के रूप में समझने की करें तो उदाहरण के लिए, यदि ग्रामीण क्षेत्रों और महिला मतदाताओं में वृद्धि अधिक है, तो इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को मिल सकता है,क्योंकि ये वर्ग अक्सर सरकारी योजनाओं से सीधे प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर, यदि शहरी क्षेत्रों, युवा मतदाताओं और पहली बार वोट देने वालों की भागीदारी में अधिक वृद्धि हुई है, तो यह विपक्ष के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि ये वर्ग परिवर्तन की मांग अधिक करते हैं। इस प्रकार, केवल उच्च मतदान प्रतिशत को देखकर किसी एक पार्टी के पक्ष में निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।क्षेत्रीय विश्लेषण भी बेहद महत्वपूर्ण है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में उच्च मतदान यह संकेत दे सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय ने रणनीतिक रूप से मतदान किया है। यह मतदान किस दिशा में गया, यह परिणामों में स्पष्ट होगा, लेकिन यह तय है कि इन क्षेत्रों का प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक रहेगा। दूसरी ओर,दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जैसे उत्तर बंगाल के क्षेत्रों में उच्च मतदान क्षेत्रीय मुद्दों,पहचान कीराजनीति और विकास के सवालों को प्रमुखता देता है।इस चुनाव में साइलेंट वोटर का प्रभाव भी चर्चा का विषय है। ये वे मतदाता होते हैं जो सार्वजनिक रूप से अपनी राजनीतिक पसंद व्यक्त नहीं करते, लेकिन मतदान के दिन निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उच्च मतदान अक्सर इस वर्ग की सक्रियता को दर्शाता है। यही कारण है कि चुनावी पंडित इस बार के परिणामों को लेकर असमंजस में हैं।

साथियों बात अगर हम अब एक और महत्वपूर्ण दावा जो सामने आ रहा है, वह यह है कि क्या इसको समझने की करें तो इलेक्शन कमिशन ऑफ़ इंडिया ने प्रत्येक चुनाव में 10 प्रतिशत अधिक मतदान सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की है। इस दावे को तथ्यों की कसौटी पर परखना आवश्यक है। चुनाव आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में मतदाता जागरूकता अभियान, डिजिटल रजिस्ट्रेशन, बूथ सुविधाओं में सुधार और महिलाओं व दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध जैसे कई कदम उठाए हैं।इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से देखा गया है, लेकिन हर चुनाव में 10 प्रतिशत की वृद्धि एक सामान्य पैटर्न नहीं है। यह वृद्धि स्थानीयराजनीतिक परिस्थितियों,मुद्दों औरप्रतिस्पर्धा की तीव्रता पर अधिक निर्भर करती है।इसी संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग का मुद्दा भी चर्चा में है। यह मांग मुख्यत: भावनात्मक और राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए व्यापक, दीर्घकालिक और बहुआयामी योगदान का मूल्यांकन किया जाता है। केवल एक चुनाव में उच्च मतदान प्रतिशत को इस सम्मान का आधार बनाना संस्थागत दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। हालांकि, यह तथ्य अवश्य है कि यदि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता, पारदर्शिता और भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उसकी सराहना की जानी चाहिए।

साथियों बात अगर हम इस पूरे परिदृश्य का अंतरराष्ट्रीय महत्व भी कम नहीं है इसको समझने की करें तो,यदि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान लगातार होने लगे,तो यह विश्व लोकतंत्र के लिए एक मिसाल बन सकता है।कई विकसित लोकतंत्रों में भी मतदान प्रतिशत 60-70 के बीच रहता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल का यह अनुभव वैश्विक स्तर पर अध्ययन का विषय बन सकता है।

अत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि, यह कहना उचित होगा कि पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह लोकतांत्रिक भागीदारी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक गतिशीलता का एक जीवंत प्रयोग बन चुका है। 93 प्रतिशत का आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जो भारतीय लोकतंत्र को जीवित और सक्रिय रखती है। अब सबकी निगाहें मतगणना के दिन पर टिकी हैं, जब यह स्पष्ट होगा कि इस ऐतिहासिक मतदान ने सत्ता की दिशा किस ओर मोड़ी है।

महिला सशक्तिकरण पर राजनीति नहीं, राष्ट्रीय सहमति जरूरी

नकुल कमलनाथ

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें चुनावी बहसों से ऊपर रखा जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व ऐसा ही एक प्रश्न है। आज महिला आरक्षण राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है— यह स्वागतयोग्य है। लेकिन इसके साथ एक गंभीर चिंता भी उभर रही है- क्या हम महिलाओं के अधिकारों को ऐतिहासिक सामाजिक सुधार की प्रक्रिया मान रहे हैं या राजनीतिक श्रेय की प्रतिस्पर्धा में बदल रहे हैं? भारतीय लोकतंत्र की शक्ति उसकी निरंतरता में है। कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन अचानक नहीं आता; वह दशकों की वैचारिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया से जन्म लेता है। महिला अधिकारों का इतिहास भी ऐसा ही है। भारत में महिला नेतृत्व किसी आधुनिक राजनीतिक प्रयोग का परिणाम नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन ने ही महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के केंद्र में स्थापित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस दौर में महिलाओं को नेतृत्व दिया जब समाज स्वयं इसके लिए तैयार नहीं था। 1917 में एनी बेसेंट का कांग्रेस अध्यक्ष बनना केवल संगठनात्मक घटना नहीं था; यह औपनिवेशिक भारत में राजनीतिक समानता की घोषणा थी। इसके बाद सरोजिनी नायडू और नेली सेन गुप्ता ने राष्ट्रीय नेतृत्व संभाला। स्वतंत्रता संघर्ष में कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू जैसी महिलाओं की सक्रिय भूमिका ने यह स्थापित किया कि भारतीय राष्ट्रवाद का स्वर स्वभावत: समावेशी था। महिला भागीदारी नारा नहीं, आंदोलन की वास्तविकता थी। विश्व के कई विकसित लोकतंत्र महिलाओं को मतदान अधिकार देने में लंबे समय तक संकोच करते रहे। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका तक में महिलाओं को मतदान का अधिकार पाने 144 साल तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भारत ने अलग रास्ता चुना। यह समझ महत्वपूर्ण है कि महिला सशक्तिकरण केवल संसद में सीटों का प्रश्न नहीं था; यह संपत्ति अधिकार, पारिवारिक न्याय और कार्यस्थल की गरिमा से जुड़ा व्यापक सामाजिक सुधार था। राजनीतिक भागीदारी का सबसे बड़ा विस्तार तब हुआ जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की पहल की। 1992-93 के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। परिणामस्वरूप लाखों महिलाएं पहली बार निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हुईं। भारतीय लोकतंत्र का सबसे व्यापक सामाजिक परिवर्तन संसद में नहीं, गांव की पंचायतों में हुआ। लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण कोई अचानक उत्पन्न विचार नहीं है। यह 1990 के दशक से राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडा रहा है। 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में राज्यसभा द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित होना उस दीर्घ राजनीतिक सहमति का महत्वपूर्ण चरण था। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में नया कानून पारित होना इसी लंबी लोकतांत्रिक यात्रा की निरंतरता है — शुरुआत नहीं। यहाँ राजनीतिक विमर्श का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। महिला सशक्तिकरण को किसी एक दल या सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना न केवल ऐतिहासिक रूप से अधूरा है बल्कि लोकतांत्रिक सहमति की भावना के भी विपरीत है। भाजपा सहित सभी दलों को स्वीकार करना होगा कि महिला अधिकारों का संघर्ष बहुदलीय, बहु-पीढ़ी और राष्ट्रीय प्रयासो का परिणाम है।

आंध्र प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक उलझन

आदिति फडणीस

आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को कई रास्ते नजर आ रहे हैं मगर चुनौती यह है कि वह किस ओर कदम बढ़ाए। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एक मुखर सहयोगी दल साबित हुआ है। मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) की सोची-समझी एवं सतर्क आलोचना को छोड़कर तेलुगु देशम अन्य सभी मुद्दों पर अपनी सहयोगी भाजपा के साथ खड़ी दिखी है। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उसके दो सदस्य हैं। नायडू ने संविधान के 131वें संशोधन विधेयक का जोरदार बचाव किया और इसे विफल करने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की।

भाजपा के लिए नायडू का रुख अन्य सहयोगियों की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण था क्योंकि आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य बनकर उभरा जिसने इस सोच को चुनौती दी कि परिसीमन से उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों को अधिक नुकसान होगा। मगर वह अकेले नहीं थे। राज्य में नायडू के कट्टर प्रतिद्वंद्वी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी ने भी विधेयक पर विपक्ष पर हमला करते हुए भाजपा का समर्थन किया। रेड्डी ने तेलुगु देशम और नायडू को निशाना बनाया है मगर भाजपा पर हमले करने से परहेज करती रही है, खासकर 2024 के लोक सभा चुनाव के बाद से। ऐसा नहीं लगता कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में लंबित पड़े मामले ही उन्हें भाजपा की आलोचना करने से रोक रहे हैं।

दो सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकतों के बीच भाजपा का समर्थन करने की मची? होड़ से भाजपा को एक ही समय में फायदे और नुकसान दोनों हो रहे हैं।

अपने तमाम प्रयासों के बावजूद आंध्र प्रदेश विधान सभा चुनावों में भाजपा का मत प्रतिशत एक अंक में ही रहा है। वर्ष 2014 में लोक सभा सीटों पर भाजपा का मत प्रतिशत 7.22 फीसदी था। वर्ष 2019 में यह घटकर लगभग 0.98 फीसदी हो गया।

वर्ष 2014 के विधान सभा चुनाव में यह 4.13 फीसदी

था और वर्ष 2019 में घट कर 0.84 फीसदी रह गया। पार्टी ने 2024 में सुधार किया और लोक सभा में 11.2 फीसदी मत प्राप्त किए मगर विधान सभा में उसका मत प्रतिशत 2.83 फीसदी पर ही रहा (वर्ष 1999 से ही राज्य में लोक सभा और विधान सभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं)।

भाजपा को लगा कि समस्या कहीं न कहीं उसकी राज्य इकाई के नेतृत्व में है। पिछले साल एक रणनीतिक निर्णय के तहत उसने डी पुरंदेश्वरी की जगह पीवीएन माधव को राज्य भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया। पुरंदेश्वरी ने भाजपा राज्य अध्यक्ष के रूप में केवल दो साल काम किया मगर कई लोगों का मानना था कि वह पारिवारिक और जातिगत संबंधों से बंधी हुई थीं (उनकी बहिन का विवाह चंद्रबाबू नायडू से हुआ है)। इसके उलट माधव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से ताल्लुक रखते थे और ओबीसी श्रेणी से हैं। वह अपने पूरे राजनीतिक जीवन में आरएसएस से जुड़े रहे। उनका काम तेलुगु देशम को नाराज किए बिना राज्य में भाजपा को मजबूत करना था ताकि 2029 में होने वाले विधान सभा चुनावों तक भाजपा की राज्य में अच्छी-खासी मौजूदगी हो जाए।

मगर यह कदम जोखिम भरा था। भाजपा वाईएसआर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर सकती। जगन मोहन रेड्डी ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं जो स्थिति को जटिल बना देती है। मगर भाजपा को उनसे रणनीतिक समर्थन लेने में कोई समस्या नहीं दिखती। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आबादी 10 फीसदी है जो गुंटूर, कृष्णा, नेल्लोर जिलों और रायलसीमा के कुछ खास निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है।

नायडू इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मुसलमानों को आश्वस्त करने की कोशिश की कि भाजपा के साथ गठबंधन करने से उनके हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने गठबंधन के सत्ता में आने पर समुदाय के लिए कई कदम उठाने का वादा किया। इनमें हज सब्सिडी, मस्जिद रखरखाव के लिए हर महीने 5,000 रुपये और दुल्हन योजना शामिल हैं जिसके तहत मुस्लिम दुल्हनों को 1 लाख रुपये देने का वादा किया गया था। उन्होंने मुसलमानों के लिए 4 फीसदी आरक्षण (ओबीसी कोटा के भीतर) बरकरार रखने का भी संकल्प लिया। भाजपा को यह बात पसंद नहीं आई मगर लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। पड़ोसी राज्य तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था 'जब तक मोदी जीवित है तब तक मैं दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा।' मगर आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ।

इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी को उन मुद्दों तक ही स्वयं को रोक कर रखना पड़ा जिन्हें लगभग सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। उदाहरण के लिए इस महीने की शुरुआत में अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा ने 'माना ऊरु-माना जेंडा' नाम से एक जनसंपर्क अभियान शुरू किया जिसका मूल उद्देश्य लोगों को राज्य के लिए केंद्र की पहल के बारे में बताना था। राज्य में भ्रष्टाचार, विशेष रूप से अमरावती के विकास में रियल एस्टेट सौदों से जुड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी मोर्चा संभाल रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं का मानना है कि किसी राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा होना हमेशा पार्टी के लिए नुकसानदेह होता है चाहे ओडिशा में बीजू जनता दल के साथ गठबंधन हो या पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ। सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की विवशता के कारण पार्टी को सत्ताधारी दल के सामने झुकना पड़ता है क्योंकि सत्ताधारी दल के पास ही राजनीतिक दबदबा होता है। अब तक पार्टी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाई है मगर आंध्र प्रदेश में सफलता हासिल के लिए उसे शायद ऐसा करना पड़ सकता है।

राघव चड्ढा की बगावत और आम आदमी पार्टी का भविष्य

कांतिलाल मांडोत

भारतीय राजनीति में दल बदल और आंतरिक बगावत कोई नई बात नहीं है लेकिन जब किसी उभरती हुई पार्टी के भीतर इस तरह का बड़ा घटनाक्रम सामने आता है तो उसके दूरगामी असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल ही में राघव चड्ढा और उनके साथ कई राज्यसभा सांसदों का आम आदमी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। यह केवल व्यक्तियों का दल बदल नहीं बल्कि एक संगठन की आंतरिक स्थिति और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

आम आदमी पार्टी ने अपने गठन के समय खुद को एक वैकल्पिक राजनीति के रूप में प्रस्तुत किया था। ईमानदारी पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों को केंद्र में रखकर इस पार्टी ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। दिल्ली में लगातार जीत और पंजाब में सरकार बनाना इस बात का प्रमाण था कि जनता ने इस पार्टी को स्वीकार किया है। लेकिन अब जिस तरह से पार्टी के भीतर असंतोष और टूट सामने आ रही है वह यह संकेत देता है कि अंदरूनी ढांचे में कहीं न कहीं कमजोरी मौजूद है। राघव चड्ढा का पार्टी से अलग होना अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ वर्षों से उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी की खबरें सामने आती रही थीं। महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थिति सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाने की कोशिश और संगठनात्मक गतिविधियों से दूरी यह सभी संकेत पहले से मौजूद थे। जब उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि संबंध सामान्य नहीं रहे हैं। इसके बाद उनका इस्तीफा और फिर भाजपा में शामिल होना एक तय दिशा की ओर बढ़ता कदम प्रतीत होता है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दो तिहाई सांसदों का गणित। भारतीय संविधान के तहत दल बदल कानून यह कहता है कि यदि किसी पार्टी के दो तिहाई सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता सुरक्षित रहती है। यही कारण है कि राघव चड्ढा ने अपने साथ पर्याप्त संख्या में सांसदों को जोड़ने का प्रयास किया। यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम भी था जिससे उनकी संसदीय स्थिति बनी

रहे। यहां सवाल उठता है कि क्या यह केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का मामला है या फिर पार्टी की कार्यप्रणाली में वास्तविक समस्याएं हैं। जब एक दो नहीं बल्कि कई सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो यह संकेत देता है कि असंतोष व्यापक है। स्वाति मालीवाल जैसे नेताओं का पहले से असहज होना और अन्य नेताओं का अचानक अलग होना यह दर्शाता है कि संवाद और विश्वास की कमी रही है। अब तुलना शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से की जा रही है। इन दोनों दलों में भी इसी तरह की टूट देखने को मिली थी जहां दो तिहाई विधायकों के अलग होने से पार्टी का नियंत्रण बदल गया। हालांकि वर्तमान स्थिति में आम आदमी पार्टी के मामले में यह टूट राज्यसभा तक सीमित है इसलिए सरकार पर तत्काल कोई खतरा नहीं है। लेकिन यदि यही स्थिति पंजाब विधानसभा तक पहुंचती है तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

पंजाब इस समय आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत आधार है। यदि वहां भी इसी तरह का असंतोष पैदा होता है और बड़ी संख्या में विधायक अलग होते हैं तो पार्टी की पहचान और अस्तित्व दोनों पर खतरा आ सकता है। इसलिए यह घटनाक्रम केवल एक संसदीय बदलाव नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं का संकेत भी है।

भारतीय जनता पार्टी के लिए यह घटनाक्रम कई मायनों में लाभकारी है। पहला राज्यसभा में उसकी संख्या बढ़ेगी जिससे विधायी प्रक्रिया में उसे मजबूती मिलेगी। दूसरा पंजाब जैसे राज्य में उसे नए चेहरों और नेटवर्क का फायदा मिलेगा। तीसरा राघव चड्ढा जैसे युवा और लोकप्रिय नेता का जुड़ना पार्टी की छवि को भी प्रभावित कर सकता है खासकर युवाओं के बीच।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता पर पड़ता है। जिस पार्टी ने खुद को वैकल्पिक और साफ सुथरी राजनीति का प्रतीक बताया था उसके भीतर इस तरह की टूट यह संकेत देती है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर हो सकता है। विपक्षी दलों को अब यह कहने का मौका मिलेगा कि यह पार्टी भी अन्य दलों की तरह ही आंतरिक संघर्ष और स्वार्थ की राजनीति से अछूती नहीं है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि राजनीति में व्यक्तित्व और संगठन दोनों का संतुलन जरूरी होता है। यदि नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कमजोर हो जाए तो असंतोष बढ़ता है। आम आदमी पार्टी के मामले में यही स्थिति दिखाई देती है जहां कुछ नेताओं को लगता है कि उनकी भूमिका कम हो रही है या उनकी बात नहीं सुनी जा रही।

आगे की राह आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं है। उसे सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करना होगा और बचे हुए नेताओं के बीच विश्वास कायम करना होगा। साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। इसके लिए पारदर्शी संवाद और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया जरूरी है।

दूसरी ओर यह भी संभव है कि यह संकट पार्टी के लिए एक अवसर साबित हो। कई बार संकट संगठन को आत्ममंथन का मौका देता है और नई दिशा तय करने में मदद करता है। यदि आम आदमी पार्टी इस स्थिति से सीख लेकर अपने ढांचे को सुधारती है तो वह फिर से मजबूत होकर उभर सकती है।

अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि राघव चड्ढा की बगावत केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक संकेत है। यह संकेत है कि किसी भी संगठन में आंतरिक संतुलन और विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। यह भी दिखाता है कि राजनीति में सिद्धांतों के साथ साथ व्यावहारिक रणनीति भी उतनी ही जरूरी है।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी इस चुनौती का सामना कैसे करती है और क्या वह अपने मूल आदर्शों को बनाए रखते हुए खुद को फिर से संगठित कर पाती है या नहीं। वहीं भारतीय राजनीति में यह घटनाक्रम एक और उदाहरण के रूप में दर्ज होगा जहां सत्ता संतुलन और रणनीति ने एक नई दिशा तय की।

एक देश, 2 मतदाता सूची, 2 किस्म के नागरिक

सनत जैन

देश में इस समय एसआईआर केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारोंके चुनाव अधिकारों को लेकर देशभर में चर्चा का विषय बनकर सामने आ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की होती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 22 से अधिक राज्यों में एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चला रखा है। अभी तक जिन राज्यों में एसआईआर हुई है, उन राज्यों में लगभग 5.50 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन्हें मतदान योग्य नागरिक नहीं माना है। जिस तरह से अभी तक एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, उसके अनुसार एसआईआर का काम पूर्ण होने पर लगभग 10 करोड़ मतदाताओं के नाम कटना तय माना जा रहा है। इसी बीच राज्य चुनाव आयोग द्वारा भी नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों के लिए अलग से मतदाता सूची तैयार की जाती है राज्य स्तर की मतदाता सूची और केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में बड़े राज्यों में करोड़ों मतदाताओं का अंतर है। इस बात को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उजागर करते हुए कहा था, राज्य की मतदाता सूची में जो नाम दर्ज हैं, उनके नाम केंद्रीय मतदाता सूची में क्यों नहीं हैं। यही सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार उठाती आ रही हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायत के चुनाव की तैयारी शुरु हो गई है। म.प्र. के राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा है, 2027 में होने वाले चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश पर जो परिसीमन हुआ था। वह मतदाता सूची राज्य चुनाव आयोग मान्य नहीं कर रहा है। जिस तरह की स्थिति देश में चुनावों को लेकर बन रही है, उसमें केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग की मतदाता सूची को लेकर विवाद की स्थिति बन रही है। राज्य सरकारों और राज्य चुनाव आयोग राज्य की तैयार मतदाता सूची से ही चुनाव कराना चाहती हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संपूर्ण राज्य में जगह-जगह मतदाता विरोध में खड़े हो जाएंगे। राज्यों में स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। ऐसी स्थिति में राज्यों की राजनैतिक एवं कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। जिस तरह के हालत अभी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यह कहने में संकोच नहीं है, भारत एक देश है। इसके बाद भी केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग की मतदाता सूची अलग-अलग है। केंद्रीय चुनाव आयोग के नियम कानून और निर्देश पर राज्यों के चुनाव आयोग काम करते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग जिन्हें मतदाता नहीं मान रहा है। राज्य का चुनाव आयोग उन्हें मतदाता मानता है। नागरिकता तय करने का अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को है। केंद्रीय गृह मंत्रालय चुप है। अब नागरिकता और मतदाता के मतदान का अधिकार तय करने का काम केंद्रीय चुनाव आयोग कर रहा है। इसको लेकर जिस तरह की अपरा तफरी सारे देश में मची हुई है, उसमें अब न्यायपालिका भी चर्चाओं में आ गई है। 10 महीने से ज्यादा हो गए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एसआईआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। न्यायपालिका अभी तक केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर कराई जा रही है। वह संवैधानिक है या नहीं इसका फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया है। सारी याचिकाएं लंबित पड़ी हुई हैं। इसी बीच राज्यों के चुनाव भी हो रहे हैं, एसआईआई भी हो रही है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह स्थिति पहली बार संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लागू होने पर देखने को मिल रही है। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजों को एसआईआर के काम में लगा दिया है। जिससे न्यायपालिका खुद पार्टी बनती हुई नजर आ रही है।

डायपर बदलते समय बरतें सावधानी

नवजात डायपर को जल्दी-जल्दी गीला करते हैं इसलिए इसको बार-बार बदलने की जरूरत पड़ती है। लेकिन छोटे बच्चों की त्वचा इतनी कोमल होती है कि उस पर किसी भी चीज से जल्द इंफेक्शन हो जाता है इसलिए डायपर बदलते समय बहुत सावधानी की जरूरत होती है। अगर छोटे बच्चे की त्वचा की देखभाल अच्छे ढंग से नहीं करेंगे तो उसकी त्वचा पर इंफेक्शन भी हो सकता हैं। नवजात के डायपर बदलते समय ध्यान इन बातों का ध्यान रखें।

- नवजात का डायपर बदलने के लिए सभी जरूरी चींजें और सामान अपने पास रख लीजिए जिससे आपको नवजात को छोड़कर बीच-बीच में कहीं जाना न पड़े।
- नवजात का डायपर बदलने के लिए सबसे पहले नवजात को प्लेन स्थान पर लिटाए। लेकिन ध्यान रखें कि जगह साफ हो।
- सफेद और हल्के कलर का डाइपर ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि ज्यादा रंगीन डायपर नवजात के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

- डायपर पहनाते समय इसे पास ही रखें लेकिन बच्चे की पहुंच से दूर हो।
- उसके बाद नवजात के दोनों पैर ऊपर करें और एक हाथ से उसके गंदे डायपर को बाहर निकालें।
- नवजात की सफाई करते वक्त यह ध्यान रखें कि उसका सिर आगे से पीछे की तरफ हो।
- गंदा डायपर निकालने के बाद नवजात को कम से कम 10 मिनट तक वैसे ही रहने दीजिए, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से सूख जाए।
- नवजात को साफ कॉटन या रूई और गर्म पानी से नमी वाले भाग को अच्छी तरह से साफ करें और पानी को पूरी तरह से सूखने दीजिए।
- डायपर बदलते समय बच्चे का ध्यान दूसरी बातों में लगाने की कोशिश करें।
- डायपर बदलते समय हमेशा अपना एक हाथ नवजात के पेट पर रखें।
- जब आप बच्चे का डायपर बदल रहे हो तो उसे खेलने के लिए खिलौने दें।
- डाइपर को शरीर पर थोड़ा ढीला कर बांधें, ताकि उसकी त्वचा पर निशान न बनें।

इन उपायों को अपनाकर आप आसानी से बच्चे के डायपर को बदल सकते हैं।

हर दिन बस 15 सेकेंड बजाएं ताली...

किसी भी मौके पर ताली बजाना हम सब की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ताली बजाने से शरीर के रोगों को भी दूर भगाया जा सकता है। दिन में सिर्फ 15 सेकेंड ताली बजाने व तलवों को नियमित रूप से पत्थर से रगड़ने से व्यक्ति खुद को रोगमुक्त रख सकता है।

ऐसे दूर होती हैं बीमारियां

व्यक्ति की हथेलियों व तलवों में शरीर के सभी अंगों के बिंदु होते हैं, जिन्हें दबाकर कई तरह के रोगों को दूर किया जा सकता है। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है जिससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। इसके अलावा अंगूठे के नीचे का स्थान दबने से रक्त की थैलियां खून को विपरीत दिशा में संचारित करती हैं जिससे धमनियों में किसी भी प्रकार की रुकावट दूर होती है। हृदय संबंधी परेशानियों में लाभ मिलता है। इससे पूरे शरीर में कंपन होता है व वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। इसी तरह पैर के तलवों को पत्थर से थोड़ी देर रगड़ने पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में दबाव बनता है जो कई रोगों से मुक्ति दिलाता है। इस उपचार में किसी प्रकार का कोई खर्च भी नहीं होता।

ऐसे बजाएं ताली

सीधे हाथ की पहली अंगुली यानी तर्जनी को दूसरे हाथ की हथेली पर चार बार जोर-जोर से चोट करें। उसके बाद तर्जनी व मध्यम दोनों को साथ में लेकर चार बार ऐसा करें। इसी प्रकार तीन अंगुलियों को साथ में लेकर फिर चारों अंगुलियों को मिलाकर ऐसा करें, अंत में दोनों हाथों से ताली बजाएं। इस दौरान आंखों को बंद रखें।

ताली बजाने के बाद दोनों हाथ गर्म व ऊर्जावान हो जाते हैं। ऐसे में ताली बजाने के बाद गहरी सांस भरते हुए मध्यम अंगुली से आंखों को छूते हुए हाथ धीरे-धीरे नीचे की ओर ले जाएं। ऐसा करने से आंखों व चेहरे पर चमक बढ़ती है।

इसलिए 15 सेकंड जरूरी

15 सेकंड की ताली की ऊर्जा रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत कर देती है जिससे शरीर को तमाम रोगों से लड़ने में मदद मिलती है।

ध्यान रहे

ताली बजाने के भी कुछ नियम होते हैं। हमेशा आसन पर खड़े होकर या पैरों में जूते पहनकर ही ताली बजाएं। जमीन पर नंगे पैर ऐसा करने से शरीर में उत्पन्न ऊर्जा जमीन में समाकर नष्ट हो जाती है। कई बार ताली बजाने से हाथों के फटने की समस्या होने लगती है इससे बचने के लिए हाथों में सरसों, नारियल या कोई अन्य तेल लगा सकते हैं।

इस फल के फायदे एक से बढ़कर एक

नाशपाती से रोगों से दूर रहा जा सकता है। इसमें विटामिन्स, खनिज, एंजाइम और फाइबर खूब पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण खूब होते हैं। नाशपाती में मौजूद पैक्टिन नामक घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। आयुर्वेद के अनुसार नाशपाती पचने में हल्की, रोगी को जल्दी ऊर्जा देने वाली, प्यास बुझाने वाली और त्रिदोष नाशक है। इसमें हाइड्रोऑक्सीनॉमिक एसिड होता है जो पेट के कैंसर को रोकने में मदद करता है। फाइबर पेट के कैंसर को बढ़ने से रोकता है व बड़ी आंत को ठीक रखता है। इसमें मौजूद फोलिक एसिड (फोलेट) गर्भवती महिलाओं के शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष से बचाता है।

यह आयरन का अच्छा स्रोत है, जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। एक गिलास नाशपाती का रस पीने से बुखार में जल्द आराम मिलता है। यह झुर्रियां, मुहांसे और त्वचा संबंधी अन्य समस्याओं को रोकने में मदद करता है। नाशपाती के पत्रों को पीसकर त्वचा पर लगाने से त्वचा विकारों में लाभ होता है। नाशपाती में बोरोन तत्व होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके सेवन से हार्ट स्ट्रोक का खतरा 50 फीसदी कम होता है व शरीर का ग्लूकोज ऊर्जा में बदल जाता है। इसमें विटामिन सी और तांबा पर्याप्त मात्रा में मिलता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नाशपाती के नियमित सेवन से मोनोपॉज के बाद महिलाओं में होने वाले कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। मधुमेह रोगियों के लिए यह स्मार्ट नाश्ता है। इससे मीठा खाने की तलब में आराम मिलता है और पोषक तत्व भी मिल जाते हैं।

ध्यान रखें: नाशपाती को अच्छी तरह धो कर छिलके समेत चबा-चबा कर खाएं। जल्दबाजी में बिना चबाए इसे खाने से पेट में दर्द हो सकता है। देर से काट कर रखी नाशपाती नहीं खानी चाहिए।

ये फायदे जानने के बाद आप भी छिदवा लेंगे कान

आप कान केवल फैशन के लिए छिदवाते रहे होंगे, लेकिन सेहत के लिए यह कितना बढ़िया है, आप नहीं जानते होंगे। कान छिदवाने से पीरियड्स प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। प्रजनन क्षमता भी अच्छी होती है। कान छिदवाने से इन्फेक्शन, हाइड्रोसील और हर्निया की समस्या दूर होती है। कान छिदवाने से दिमाग का विकास भी होता है। हैरानी होगी आपको यह जानकर कि कान के दोनों ओर एक पॉइंट होता है जिसका संबंध दिमाग से होता है। एक्यूप्रेशर के इलाज में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे न केवल दिमागी विकास होता है, बल्कि याददाश्त भी बढ़ती है। कान के बीच का हिस्से का संबंध आंखों की रोशनी से भी होता है। ऐसे में आंखों की रोशनी बढ़ानी है, तो कान छिदवा लें। सुनने की क्षमता भी बढ़ती है। कान छिदवाने वाली जगह पर दो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। पहला मास्टर सेंसोरियल और दूसरा मास्टर सेरेब्रल। ये सुनने की क्षमता सही रखते हैं। एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट्स की मानें तो टिटनस को दूर रखने के लिए भी कान छिदवाना बिल्कुल सही रहता है। हिस्टीरिया की समस्या को भी दूर रखता है। कान छिदवाने से तनाव, डिप्रेशन भी दूर होता है। डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखना है, तो कान छिदवा लें। वजन घटाने का भी यह एक अच्छा विकल्प है। कान पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होने के कारण दबाव पड़ता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है।

बरगद के दूध में छिपे हैं बड़े गुण

वट वृक्ष (बरगद) की तासीर ठंडी होती है जो कफ, पित्त की समस्या को दूर कर रोगों का नाश करती है। बुखार, स्त्री रोग संबंधी समस्याएं, उल्टी व त्वचा के रोगों में वट वृक्ष के पत्तों, जड़ों और दूध का प्रयोग फायदेमंद होता है।

पत्ते हैं उपयोगी

वट की कोपलें चेहरे की कांति बढ़ाने का काम करती हैं। बरगद की जड़ों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसकी ताजी जड़ों को कुचल कर चेहरे पर लगाएं। झुर्रियां कम हो जाएंगी। इसके पत्तों को तवे पर सेककर सहने योग्य स्थिति में फोड़ों के ऊपर बांधने से लाभ मिलता है। इसके पत्तों की लुग्दी बनाकर शहद और शक्कर के साथ लेने से नकसीर की समस्या में आराम मिलता है। वट के बीजों को पीसकर पीने से उल्टी आने की समस्या दूर होती है।

दूध भी गुणकारी

जिस दांत में कीड़ा लग गया हो वहां इसके दूध में भीगा फोहा रखने से लाभ होता है। लगभग 10 ग्राम बरगद की छाल, कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च बारीक पीसकर पाउडर बना लें। यह मंजन करने पर दांतों का हिलना, सड़न, बदबू दूर हो जाती है। वट का दूध, शक्कर के साथ लेने से बवासीर में लाभ होता है। वट का दूध लगाने से सूजन कम हो जाती है। वट के दूध का लेप कमर पर करने से दर्द में लाभ होता है। फटी पड़ी एड़ियों पर बरगद का दूध लगाया जाए, तो काफी राहत मिलती है। बरगद की ताजा कोमल पत्तियों का पाउडर बनाकर खाने से मेमोरी अच्छी होती है। इसके पत्तों की राख को अलसी के तेल में मिला कर लगाने से सिर के बाल उग आते हैं। इसके कोमल पत्तों को तेल में पकाकर लगाने से सभी केश के विकार दूर होते हैं। जले हुए स्थान पर इसके कोमल पत्तों को पीसकर दही में मिलाकर लगाने से शान्ति प्राप्त होती है।

वर्कआउट के लिए सही कपड़े

आप फिट रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते। जिम में कई घंटों तक पसीना बहाते हैं, लेकिन सही एक्सरसाइज के साथ ही वर्कआउट के लिए सही कपड़ों का चुनाव भी बहुत जरूरी है। तभी आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे और दूसरों के सामने असहजता या शर्मिंदगी से भी बच सकेंगे।

कैसी हो फिटिंग

एक्सरसाइज टाइप के मुताबिक ही आपके कपड़ों की फिटिंग होनी चाहिए। जैसे हैवी एक्सरसाइज या उपकरणों के साथ कसरत करते वक्त थोड़े ढीले और कंफर्टेबल शॉर्ट/लोवर के साथ टी-शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन योगा या पिलाटे जैसी वर्कआउट के लिए स्ट्रेचेबल और फिट आउटफिट पहनें। इनके लिए जिम पैंट्स या योगा पैंट्स पहनें। हर मौसम में एक्सरसाइज के लिए अलग तरह के कपड़े पहनें, ताकि मौसम की मार आपकी सेहत पर न पड़े।

बॉडी के हिसाब से

अकसर लोगों को जिम में पसीने की बदबू परेशान करती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए वे सुगंधित परफ्यूम और लोशन का इस्तेमाल करते हैं। वर्कआउट करते समय जब आपकी बॉडी में गर्मी पैदा होने लगती है और पसीना आता है तो तेज सुगंध वाले परफ्यूम का अरोमा और बढ़ जाता है। जिम में लोशन का इस्तेमाल करने से बचें। लोशन लगाने से पसीना आने पर आपके हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे कुछ समय बाद ही जिम में वर्कआउट करने में मुश्किल होती है और यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। कहने का मतलब है कि वर्कआउट करते समय आपके हाथ जगह जगह लगते हैं जिससे आपके द्वारा पकड़ी गई हर चीज चिपचिपी हो जाती है। आपके चेहरे पर लगा लोशन पसीने के साथ बहकर आंखों में जलन पैदा कर सकता है इसलिए यदि लोशन या परफ्यूम लगाना ही चाहते हैं तो उसकी गंध तीव्र न हो।

कैसा हो रंग

नियोन रंग के कपड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह आप पर फबे। हमेशा गाढ़े रंग के कपड़ों का ही चुनाव करें। ऐसे स्पोर्ट्स शूज चुनें जो वर्कआउट करते समय पैरों के लिए सुरक्षित हों। इसके अलावा रनर्स अपने लिए स्पेशल शूज चुन सकते हैं। जूतों का सोल घिसने से पहले उसे रिजेक्ट कर दें वरना आपके ज्वाइंट डेमेज हो सकते हैं। आप जिम जाने के लिए छोटी स्लिव्स वाले टॉप पहन सकते हैं जो टाइट न हो। कंधों को कवर करने वाले कपड़े पहने, जो ज्यादा टाइट न हों। ढीले-ढाले कपड़े पहनकर आप आसानी से न केवल अपने हाथों को मोड़ सकते हैं, आपको वेट-लिफ्टिंग में भी कोई परेशानी नहीं होती।

कॉटन के कपड़े

खुद को कूल रखने के लिए कॉटन के कपड़े चुनें। एक्सपर्ट आपको उन कॉटन के कपड़ों को चुनने की सलाह देते हैं जो लाइकरा या पॉलिएस्टर से बने होते हैं। यदि आप स्पेंडेक्स को पहनकर कम्फर्टेबल फील करते हैं तो जिम वियर के लिए स्पेंडेक्स बहुत ही बढ़िया चुनाव है। अगर आपको ज्यादा पसीना नहीं आता तो आप कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं क्योंकि गीले होने पर वह बदन में चिपकते नहीं हैं।

रेसिपी

पुदीना पूरी

सामग्री

1/2 कप बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते
1 कप गेहूं का आटा
1 टेबल-स्पून तेल
1/2 टी-स्पून

विधि

पुदीने की पत्तियों को धोकर बारीक काट लें। पुदीना की पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले गेंहू के आटे को एक बड़े बाउल में छानकर निकाल लें और छने हुए आटे में कटी हुई पुदीना की पत्तियां, अजवाइन, जीरा, बेकिंग सोड़ा, कटी हुई हरी मिर्च और नमक डालकर थोड़े-थोड़े पानी से कड़ा पूड़ी जैसा आटा गूंध लें और अब आटे को ढ़ककर करीब 10 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद गैस पर कड़ाही में तेल डालकर गरम करने के लिए रख दें। आटे से छोटी-छोटी लोइयां बना लें और अब प्रत्येक लोई को गोल पूड़ी के आकार में बेल लें। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तब एक- एक पूड़ी को गरम तेल में डालकर दोनों तरफ पलट कर डीप फ्राई करके नैपकीन पेपर पर निकाल लें, इसी तरह से सभी पुदीना पूड़ियों को तलकर तैयार कर लें। स्वादिष्ट पुदीना की पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसे आलू की सब्जी या फिर दही और आचार के साथ खा सकते हैं।

पनीर पालक मेथी

सामग्री

पालक - 250 ग्राम (बारीक कटी हुई), मेथी - 250 ग्राम (बारीक कटी हुई), पनीर - 250 ग्राम, तेल - 2-3 टेबल स्पून, हींग - 1 चुटकी, जीरा - आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर - चौथाई छोटा चम्मच, धनियां पाउडर - 1 छोटा चम्मच, टमाटर - 1 (बारीक कटा हुआ), लाल मिर्च पाउडर - चौथाई छोटा चम्मच, हरी मिर्च - 2 (बारीक कटी हुई), नमक - 3/4 छोटी चम्मच या स्वादानुसार चीनी - आधा छोटा चम्मच (यदि आप चाहें)

विधि

पनीर को 1-1 इंच के चौकोर टुकड़ों में काट लीजिए। पैन में 2 टेबल स्पून तेल डालकर गरम कीजिए। तेल गरम होने पर पनीर के टुकड़े इसमें डाल दीजिए और दोनों और से हल्के ब्राउन होने तक सेक लीजिए। सिके हुए पनीर के टुकड़ों को प्लेट मे निकाल लीजिए। पैन में तेल बचा है, 1 टेबल स्पून तेल और डाल दीजिए, गरम तेल में जीरा डाल दीजिए। जीरा भूनने पर इसमें हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनियां पाउडर, बारीक कटे हुए टमाटर डाल कर, मसाले को थोड़ा सा भून लीजिए। भुने मसाले में बारीक कटी हुई मेथी, बारीक कटी हुई पालक, नमक, लाल मिर्च पाउडर और चीनी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सब्जी को मीडियम आग पर ढ़ककर के 5 मिनट के लिए पकने दीजिए और उसके बाद चैक कीजिए। सब्जी पक चुकी है, इसमें पनीर के टुकड़े डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सब्जी को एक बार फिर ढ़ककर के 2-3 मिनट के लिए धीमी आग पर पकने दीजिए। पनीर मेथी पालक सब्जी बनकर तैयार है, इसे प्याले में निकाल लीजिए। सब्जी को आप परांठे, चपाती, नॉन या चावल किसी के भी साथ भी खा सकते हैं।

इस आश्रम में आते हैं सबसे ज्यादा अमेरिकी

पिछले दिनों अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत में एक मंदिर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की सलाह पर भारत के इस मंदिर में गए थे। जुकरबर्ग ने इस मंदिर का नाम नहीं बताया था लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मंदिर नैनीताल के पास पंत नगर में बाबा नीम करौली के आश्रम में ही था। इसी आश्रम में 1974 में स्टीव जॉब्स आए थे। नीम करोली बाबा का कैंची धाम आश्रम नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर नैनीताल-अलमोड़ा रोड़ पर समुद्र तल से 1400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 10 सितम्बर 1973 में वृन्दावन की पावन भूमि पर नीम करौली बाबा का निधन हो गया लेकिन कैंची धाम आश्रम में अब भी विदेशी आते रहते हैं। बताया जाता है कि सबसे ज्यादा अमेरिकी ही इस आश्रम में आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच है। नीम करौली बाबा के कैंची धाम आश्रम की भौगेलिक स्थिति पूर्णतः वास्तुनुकूल है, क्योंकि आश्रम की दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में ऊंचे-ऊंचे पहाड़ है और जहां आश्रम बना है उसकी उत्तर एवं पूर्व दिशा में पहाड़ों के तीखे ढलान के कारण बहुत नीचाई है। पहाड़ की इस नीचाई के बाद उत्तर एवं पूर्व दिशा में ही क्षिप्रा नदी भी बह रही है। फेंगशुई का एक सिद्धांत है कि, यदि पहाड़ के मध्य में कोई भवन बना हो, जिसके पीछे पहाड़ की ऊंचाई हो, आगे की तरफ पहाड़ की ढलान हो, और ढलान के बाद पानी का झरना, कुण्ड, तालाब, नदी इत्यादि हो, ऐसा भवन प्रसिद्धि पाता है और सदियों तक बना रहता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रो. गोबर्धन दास से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रोफेसर गोबर्धन दास से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत जीवन बेहद प्रेरणादायक है। उन्होंने आगे कहा कि उनका समृद्ध कार्य और विद्वत्ता नीति निर्माण की संरचना को समृद्ध करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आज सुबह प्रो. गोबरधन दास से मुलाकात हुई। उनका व्यक्तिगत जीवन बेहद प्रेरणादायक है। उनके सामने आने वाले हर संघर्ष ने समाज की सेवा करने और उसे कष्टों से मुक्त करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। यह उनके जन स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए योगदान में स्पष्ट रूप से झलकता है। उनका समृद्ध कार्य और विद्वत्ता हमारी नीति निर्माण संरचना को समृद्ध करेगी।' 25 अप्रैल को, नीति आयोग के नव नियुक्त सदस्य गोबरधन दास ने राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय पुनरुद्धार के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की थी।

बंगाल में सियासी संग्राम तेज उदित राज का ममता पर हमला

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने राज्य की मौजूदा स्थिति के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राज्य में विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उदित राज ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक गतिविधियां करने से रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी उन पर हमला किया जाता है। उनके मुताबिक, यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक कार्यकर्ता की मौत को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की कथित हत्या की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूटी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि वह आबकारी मामले में व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से उनके समक्ष पेश नहीं होंगे। पार्टी ने सोमवार को यह जानकारी दी। केजरीवाल ने पत्र में लिखा, ''न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट गई है। इसलिए, मैंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया है।'' केजरीवाल ने लिखा, जस्टिस स्वर्णकांता से इंसाफ़ मिलने की मेरी उम्मीद टूट गई है। मैंने गांधीजी के सत्याग्रह को फॉलो करने का फ़ैसला किया है। मैंने अंतरात्मा की आवाज़ पर फ़ैसला किया है। मैं जस्टिस स्वर्णकांता के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार रखूंगा। 20 अप्रैल को हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरों की उस अर्ज़ी को खारिज कर दिया था।

चुनाव से पहले बसपा ने तीन नेताओं को किया निष्कासित

लखनऊ। बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के तीन वरिष्ठ नेताओं को निष्कासित कर बड़े उलटफेर को अंजाम दिया है। तीनों नेताओं का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरा दखल होने की वजह से पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासकर धर्मवीर अशोक और जयप्रकाश का निष्कासन कार्यकर्ताओं के असंतोष की वजह बनता जा रहा है। इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बसपा में पूर्व मंत्री धर्मवीर अशोक की गिनती पार्टी संस्थापक कांशीराम के साथियों में होती है। मायावती ने उनको कई राज्यों की जिम्मेदारी भी दे रखी थी। संगठन में उनकी गहरी पैठ होने की वजह से वह खासे लोकप्रिय भी थे। अचानक उनका निष्कासन पश्चिमी उप्र के साथ कई राज्यों में बसपा के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वहीं जयप्रकाश की बसपा में लंबे समय के बाद वापसी हुई थी। निष्कासित होने के बावजूद वह पश्चिमी उप्र में युवाओं को बसपा से जोड़ते रहे।

पश्चिम बंगाल चुनाव में फिर हिंसा, जवान को लगी गोली

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार पवन सिंह के आवास के बाहर हुई गोलीबारी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का एक जवान घायल हो गया जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने घटना पर रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह घटना रविवार को ऐसे समय में हुई जब 29 अप्रैल को राज्य में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान होना है। एक अधिकारी ने बताया कि घायल जवान की पहचान योगेश शर्मा के रूप में हुई है, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह की सुरक्षा टीम में थे। उन्होंने बताया कि शर्मा को पैर में गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने घटना पर रिपोर्ट मांगी है, जबकि पुलिस ने कहा है कि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि गोली किसने चलाई।

प्रधानमंत्री ने बैरकपुर से बंगाल को दी पांच गारंटी

पढ़ाई, लिखाई और दवाई हमारी प्राथमिकता : मोदी

बैरकपुर (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। आज प्रचार का अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का प्रचार करने बैरकपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा, 1857 में इसी बैरकपुर की धरती ने आजादी की पहली लड़ाई को ताकत दी थी। यही धरती आज बंगाल में परिवर्तन की राह को और प्रशस्त कर रही है। भाजपा के चुनावी नारे और बंगाल में बदलाव की बयार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने रैली में कहा कि बंगाल में हर ओर एक ही नारा सुनाई दे रहा है पलटनो दरकार, चाई बीजेपी सरकार। यानी जनता बदलाव चाहती है और भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है।

रैली को चुनाव प्रचार की अंतिम सभा बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूरे राज्य में लोगों का मूड देखकर उन्हें विश्वास है कि 4 मई को नतीजे आने के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और वह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने फिर बंगाल आएंगे।

उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मिले जनसमर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि रैलियों और रोड शो के दौरान लोगों द्वारा दिए गए संदेश, पत्र और चित्र उनके लिए बेहद खास हैं। वह रात में समय निकालकर इन भावनाओं को समझते हैं और लोगों के संदेशों को पढ़ते हैं। अपने लंबे राजनीतिक सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह पिछले कई दशकों से देशभर में लगातार काम कर रहे हैं और पार्टी द्वारा सौंपी गई हर जिम्मेदारी को निभाते आए हैं। उन्होंने कहा कि जनता ही उनका परिवार है और उनके बीच रहकर उन्हें सुकून मिलता है।

पीएम मोदी ने दावा किया कि राज्य में बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती से उनका जुड़ाव बेहद खास है और यहां के अनुभवों को

वह अपने जीवन का आशीर्वाद मानते हैं। उनके अनुसार, जिस तरह जनता बड़ी संख्या में सामने आ रही है, उससे स्पष्ट है कि बैरकपुर समेत पूरा बंगाल बदलाव के लिए तैयार खड़ा है।

पीएम मोदी ने अपने चुनावी रोड शो और रैलियों को तीर्थ यात्रा जैसा अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और लगातार कार्यक्रमों के बावजूद उन्हें थकान महसूस नहीं हुई, क्योंकि लोगों का उत्साह उन्हें लगातार ऊर्जा देता रहा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी दूर-दूर तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जिसे देखकर वह फिर से पूरे जोश के साथ उनके बीच पहुंच जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि मां काली के भक्तों के बीच जाने से उन्हें विशेष ऊर्जा मिलती रही।

पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता के लिए पांच अहम गारंटियों का एलान किया। उन्होंने कहा कि ये वादे बंगाल के विकास और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए हैं। पीएम मोदी की पहली गारंटी के तहत रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले लोगों को बैंक के जरिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि उनका कारोबार मजबूत हो सके। दूसरी गारंटी में उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकारी भर्तियां तय समयसीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएंगी।

तीसरी गारंटी में रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को सीधे नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। वहीं चौथी गारंटी के तहत राज्य में सातवें वेतन आयोग को तुरंत लागू करने का वादा किया गया। पांचवीं और अहम गारंटी में पीएम मोदी ने कहा कि राज्य से पलायन रोकने के लिए गांवों में 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम मिल सके।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के पास बंगाल के विकास के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं है। पार्टी ने अपने 15 साल के शासन का कोई ठोस हिसाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि न तो उनके पास विजन है और न ही कुछ करने की नीयत। पीएम मोदी ने आगे कहा कि टीएमसी के शासन में सिंडिकेट राज और अवैध गतिविधियां बढ़ी हैं, जिन्हें खत्म करना जरूरी है।

रैली से पहले पीएम मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक थंथानिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना कर मां काली का आशीर्वाद भी लिया। यह मंदिर 300 साल से अधिक पुराना और श्रद्धालुओं के बीच बेहद आस्था का केंद्र माना जाता है। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार कौस्तव बागची, तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा विधायक राज (राजू) चक्रवर्ती और सीपीआई(एम) के सुमन रंजन बंद्योपाध्याय के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। बैरकपुर विधानसभा सीट उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है और यहां दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

7 आप सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी

राज्यसभा में बढ़ी भाजपा की ताकत, दो तिहाई बहुमत के करीब पहुँचा एनडीए

नईदिल्ली। राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के भाजपा में विलय को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सदन में भाजपा सदस्यों की संख्या बढ़कर 113 हो गयी है जबकि आप सदस्यों की संख्या घटकर तीन हो गयी है। वहीं अब राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कुल संख्या 141 से बढ़कर 148 तक पहुंच गई है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा उच्च सदन में दलों की स्थिति को अपडेट किए जाने के साथ ही यह परिवर्तन आधिकारिक रूप से दर्ज हो गया है।

हम आपको बता दें कि यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब कुछ दिन पहले राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाया गया था। इसके बाद उन्होंने और छह अन्य सांसदों ने आम आदमी पार्टी से अलग होने और भारतीय जनता पार्टी में विलय का निर्णय लिया। उनके साथ स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता और विक्रम साहनी भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को सातों सांसदों ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर उन्हें विलय के बाद भाजपा सांसद माने जाने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को राज्यसभा के सभापति को एक पत्र लिखकर दल बदल करने वाले सातों सांसदों की सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध किया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने सभापति राधाकृष्णन को पत्र देकर उच्च सदन में पार्टी के उन सातों सांसदों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया है, जिन्होंने हाल ही में आप छोड़कर भाजपा में विलय की घोषणा की थी।

हम आपको याद दिला दें कि पिछले सप्ताह राघव चड्ढा ने एक प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया था कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दो तिहाई सदस्यों ने संविधान के प्रावधानों

का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी में विलय का फैसला किया है। विशेषज्ञों के अनुसार, वर्ष के अंत तक राज्यसभा की 30 से अधिक सीटें खाली होने वाली हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कम से कम पांच अतिरिक्त सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे पार्टी दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंच सकती है, जो कि 163 का आंकड़ा है।

दूसरी ओर, राघव चड्ढा ने अपने फैसले को लेकर उठ रही आलोचनाओं का जवाब भी दिया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें लोगों के संदेश मिल रहे हैं, जिनमें कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं तो कुछ उनके निर्णय के कारण जानना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन के 15 महत्वपूर्ण वर्ष आम आदमी पार्टी को समर्पित किए और वह इसके संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। उनका कहना था कि वह राजनीति में कॅरियर बनाने नहीं आए थे, बल्कि एक विचारधारा के साथ जुड़े थे।

हालांकि, उन्होंने पार्टी की वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। उनके अनुसार, पार्टी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी का कार्य वातावरण विषाक्त हो गया है, जहां काम करने और संसद में बोलने तक पर रोक लगाई जाती है। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें लगने लगा था कि वह सही व्यक्ति हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने कई विकल्पों पर विचार किया, जिनमें राजनीति छोड़ना, पार्टी के भीतर सुधार लाने की कोशिश करना या किसी अन्य मंच से जुड़ना शामिल था। अंतत: उन्होंने नया राजनीतिक रास्ता चुनने का निर्णय लिया।

उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि यह फैसला किसी दबाव या डर के कारण नहीं लिया गया, बल्कि निराशा और असंतोष के चलते लिया गया है। उनका कहना था कि एक या दो लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन सात लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते।

अभी हमारी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई : संजय सिंह

सात राज्यसभा सांसदों के आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल होने को राज्यसभा सभापति की मंजूरी मिल गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा, भाजपा ने अशोक मित्तल पर छापे पड़वाए थे। भाजपा ने कहा था कि वे बहुत भ्रष्ट हैं। आज अशोक मित्तल भाजपा में चले गए हैं।

संजय सिंह ने कहा, सातों सांसदों ने जो विलय का पत्र दिया है, चेयरमैन ने उसका संज्ञान लिया है। मैंने उन्हें पत्र लिखा है कि संविधान की 10वीं अनुसूचि के मुताबिक इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे इस पर फैसला देंगे। अभी तक चेयरमैन साहब की ओर से हमारी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। बता दें कि राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी (आप) के सात सांसदों के भाजपा में शामिल होने को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद उच्च सदन में आप की स्थिति कमजोर हो गई है। संसद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन सातों सांसदों को अब भाजपा सदस्य के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। सूत्रों के अनुसार, इन सभी सांसदों ने शुक्रवार को सभापति को पत्र देकर स्वयं को भाजपा का हिस्सा मानने की मांग की थी।

खेल
प्रमुख समाचार

प्लेऑफ के लिए पंजाब सहित चार टीमें प्रबल दावेदार

मुम्बई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19 वें सत्र के करीब आधे मुकाबले हो गये हैं। अभी तक कुल 70 मैचों में से 36 मुकाबले पूरे हो गये हैं। इससे बाद प्लेऑफ के लिए अब टीमों के बीच मुकाबला और कड़ा हो गया है। पंजाब किंग्स की टीम इस सत्र में सबसे अधिक अंक लेकर शीर्ष पर चल रही है। पंजाब ने अभी तक खेले गए 7 मैचों में से 6 में जीत दर्ज की है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनका एक मैच बारिश के कारण नहीं हो पाया था। इस प्रकार कुल 13 अंकों के साथ, पंजाब अंक तालिका में शीर्ष पर है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए नंबर एक पर है। अगले दो से तीन मैचों में ही उसे नॉकआउट दौर का टिकट मिलना तय है।

वहीं पंजाब के अलावा, अंक तालिक में शी-4 में शामिल गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स भी शामिल हैं। राजस्थान और हैदराबाद ने 8-8 मुकाबले खेल लिए हैं, जबकि बेंगलुरु ने अभी तक 7 मैच खेले हैं। इन तीनों टीमों के भी 10-10 अंक हैं, जिससे ये प्लेऑफ की दौड़ में बचे हुए तीन स्थानो के लिए सबसे बड़े दावेदार के तौर पर उभरे हैं। इनका जबरदस्ता प्रदर्शन इन्हें इसके योग्य बनाता है।

वहीं चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके), दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के लिए प्लेऑफ की में पहुंचना कठिन है। इन तीनों ही टीमों के 7-7 मैचों के बाद 6-6 अंक हैं। जबकि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 अंकों की जरुरत होती है। ऐसे में चेन्नई, दिल्ली और गुजरात को प्लेऑफ के लिए अपने बचे हुए 7 में से कम से कम 5 मैच जीतने होंगे, जो अभी संभव नजर नहीं आ रहा है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 639 अंक उछला निफ्टी 24092 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में पॉजिटिव रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन यानी सोमवार (27 अप्रैल) को मजबूती के साथ बंद हुए। तिमाही नतीजों के दम पर फार्मा और आईटी शेयरों के साथ रियल्टी स्टॉक्स में खरीदारी से बाजार चढ़कर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी तेजी से भी बाजार को मजबूत सपोर्ट मिला। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 76,856 अंक पर खुला। शुक्रवार को यह 76,664 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 77,420 अंक तक चढ़ गया था। अंत में यह 639.42 अंक या 0.83 फीसदी की बढ़त लेकर 77,303.63 पर ट्रेड कर रहा था। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 23,945 पर खुला और खुलते ही 24 हजार के पार चला गया। कारोबार के दौरान यह 24,130 अंक के इंट्रा-डे हाई तक गया। अंत में यह 194.75 अंक या 0.81% चढ़कर 24,092 पर बंद हुआ।

5 साल में 1.10 लाख पर मिलेगा करीब 38 हजार ब्याज

नईदिल्ली। अगर आप बिना जोखिम और सुरक्षित रिटर्न चाहते तो बैंक ऑफ बड़ोदा एफडी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ोदा की 5 साल की एफडी स्कीम को लेकर काफी चर्चा है, जिसमें 1,10,000 रुपए जमा करने पर अच्छा खासा ब्याज मिल सकता है। बैंक की मौजूदा ब्याज दरों के अनुसार, 5 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी पर आम ग्राहकों को करीब 6% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को इस पर लगभग 7% ब्याज मिलता है। एफडी की अवधि कम से कम 7 दिन और अधिकतम 10 साल तक हो सकती है, लेकिन यहां हम 5 साल की अवधि पर फोकस कर रहे हैं। अगर कोई सामान्य ग्राहक 1,10,000 रुपए की एफडी 5 साल के लिए करता है, तो 6% ब्याज दर के हिसाब से उसे करीब 38,154 रुपए का ब्याज मिलेगा।

गर्मी में आइसक्रीम-चॉकलेट और ड्रिंक्स हुई महंगी

नईदिल्ली। भीषण गर्मी के बीच ठंडी चीजों की मांग चरम पर है लेकिन इसी समय लोगों को एक और झटका लगा है। आइसक्रीम, चॉकलेट और ठंडे पेय पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पश्चिम एशिया में जारी ईरान-इजरायल युद्ध के चलते सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसका असर अब सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री महंगी हो गई है। साथ ही चॉकलेट और आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाला कोको और ड्राई फ्रूट्स भी आयात होते हैं, जिनकी लागत में तेजी आई है। दिल्ली के थोक बाजार चावड़ी बाजार के व्यापारियों के अनुसार, पिछले दो महीनों में सूखे मेवों की कीमतों में 20-22% तक बढ़ोतरी हुई है। समुद्री परिवहन महंगा होने और बीमा लागत बढ़ने से आयातित सामान की कीमतें बढ़ी हैं।

शुक्रवार यानि 1 मई को बैंक रहेंगे बंद

नई दिल्ली। अगर इस हफ्ते आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो पहले छुट्टियों का शेड्यूल जरूर देख लें। अप्रैल के आखिरी और मई की शुरुआत वाले सप्ताह में कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो सकता है। 1 मई (शुक्रवार) को महाराष्ट्र डे और इंटरनेशनल लेबर डे के मौके पर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी इस दिन बैंक अवकाश रहेगा। हालांकि, सभी राज्यों में यह छुट्टी लागू नहीं होगी और कुछ जगहों पर बैंक सामान्य रूप से खुले रह सकते हैं। इसके बाद 3 मई को रविवार होने के कारण पूरे देश में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बैंक केवल दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं।

युद्ध से सबक लेकर भारत को अपनी आर्थिक नीतियां सुधारने की जरूरत

कनिका दत्ता

संकट प्रबंधन के मामले में भारत सरकार का प्रदर्शन मिलाजुला रहा है। कुछ आपात स्थितियों से निपटने के वर्षों के अनुभव ने प्रशासनिक तंत्र को प्रबंधन के उपाय पहले से ही कर लेने की कला सिखाई है। नतीजतन भारत में सूखे की मार अब उतनी गंभीर रूप से नहीं पड़ती (जैसा कि इस वर्ष पड़ने की आशंका है)। एहतियाती उपायों से यह सुनिश्चित होता है कि चक्रवात के तटीय इलाकों में आने पर बड़ी संख्या में लोगों की जान न जाए, और ताप ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोयले के परिवहन को कुशलता से पुनर्व्यवस्थित करने से हमें पिछली तीन भीषण गर्मियों में मांग में आई अचानक वृद्धि से निपटने में मदद मिली है।

यह सच है कि इन संकटों से निपटने के तरीके पूरी तरह से कारगर नहीं होते, लेकिन हर साल अफसरशाही अपने अनुभवों से सीख लेती है। दुख की बात यह है कि राजनीतिक तंत्र संकटों से निपटने के तरीकों को सार्थक और स्थायी रूप से बदलने में अक्सर सक्षम नहीं होता। हालांकि सरकारें तात्कालिक संकट से निपटने में फुर्ती दिखाती हैं, लेकिन वे स्थायी सुधारों के अवसरों को शायद ही कभी पहचान पाती हैं। पिछली बार जब ऐसा हुआ था, तब देश आर्थिक उदारीकरण के रास्ते पर चल पड़ा था।

पश्चिम एशियाई युद्ध, नीति निर्माण और आर्थिक खर्च की प्राथमिकताओं में बदलाव लाने का एक और अवसर प्रदान करता है।

जब होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ, तो कर्तव्य भवन ने रसोई गैस की कमी से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग को सीमित करके, आपूर्ति की राशनिंग करके और पेट्रोल पंप की कीमतों को स्थिर रखने के लिए करों में

कटौती करके त्वरित कदम उठाए।

विधान सभा चुनावों से पहले ये दूरदर्शी कदम हैं, लेकिन ये ईंधन की कमी के कारण ढाबों और छोटे व्यवसायों के बंद होने से उत्पन्न बेरोजगारी के दीर्घकालिक प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं।

संक्षेप में, भारतीय अब रणनीतिक प्राकृतिक गैस भंडारण सुविधाओं के निर्माण में विफलता के परिणामों का सामना कर रहे हैं, जबकि सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी और पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस के विस्तार के माध्यम से मांग बढ़ाने का प्रयास किया, जिनमें से दोनों ही ज्यादातर आयातित हैं। रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार का निर्माण इस संकट की मांग के अनुरूप खर्च में एक अन्य प्राथमिकता है। बफर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या वे पर्याप्त हैं, यह एक खुला प्रश्न है।

खरीफ का मौसम नजदीक आने के साथ ही, होर्मुज स्ट्रेट में आपूर्ति बाधित होने के कारण भारतीय किसानों को उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू उत्पादन में गिरावट और सबसे अधिक सब्सिडी वाले पोषक तत्त्व, आयातित यूरिया की बढ़ती कीमतों के कारण, सरकार को अपने पहले से ही भारी उर्वरक सब्सिडी बिल में और भी अधिक वृद्धि की आशंका है।

इससे उत्पादकों से किसानों को सब्सिडी देने की दिशा में बदलाव करने का अच्छा अवसर मिलेगा। कृषि अर्थशास्त्रियों द्वारा लंबे समय से सुझाया गया एक सुझाव यह है कि उर्वरक लागत के लिए किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से सरकारी खजाने को सालाना लगभग 75,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। इससे सब्सिडी योजनाओं के साथ होने वाले अपरिहार्य नुकसान को रोका जा सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने, रणनीतिक जीवाश्म ईंधन भंडार बनाने, उर्वरक सब्सिडी के बोझ को कम करने या इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे मामलों में, सरकार के पास इस संकट का लाभ उठाकर स्थायी फायदे हासिल करने का एक अनूठा अवसर है और उसके पास जनादेश भी है। उसे इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।?

महिला आरक्षण पर निगम में जमकर हंगामा और धक्का-मुक्की

रायपुर। नगर निगम में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। महिला सशक्तिकरण और आरक्षण को लेकर मेयर मीनल चौबे के साथ बीजेपी पार्षदों ने पहले परिसर में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद बैठक शुरू होने पर भी कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों ने बात रखी। हद तो तब हो गई जब नेता प्रतिपक्ष के बयान पर ना सिर्फ सदन में हंगामा हुआ बल्कि धक्का मुक्की और माइक छीनने तक की नौबत आ गई।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ये अंग्रेजों के मुखबिर

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने महिला सशक्तिकरण पर अपनी बात रखी। इस बीच उन्होंने कहा कि ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे। यह शब्द बोलते हैं भाजपा पार्षदों ने हंगामा कर दिया। कुछ पार्षद कुर्सी छोड़कर नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंच गए और उनके सामने खड़े होकर जोरदार नारेबाजी की। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष का माइक भी छीना गया।

सदन की कार्यवाही स्थगित

नेता प्रतिपक्ष के साथ भाजपा पार्षदों ने की धक्का मुक्की की जिसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद आकाश तिवारी ने कहा कि मैंने कहा ये लोग मुखबिर हैं, मैंने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया तो फिर ये लोग क्यों चिढ़ने लगे। क्योंकि बीजेपी ही अंग्रेजों की मुखबिर है और रहेगी।

कांग्रेस पहले गोरों से लड़ी थी अब चोरों से लड़ेगी। सदन में चर्चा महिला सशक्तिकरण पर थी और ये लोग विरोध और हंगामा मुखबिर के मुद्दे पर कर रहे हैं- आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष

बीजेपी का जवाब

एमआईसी सदस्य सरिता दुबे ने कहा कि चर्चा महिला सशक्तिकरण को लेकर थी। कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर उस बिल को पास होने नहीं दिया इसी को लेकर हम लोगों ने सदन में अपने विचार रखे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने गलत और निंदनीय बयान दिया है।

इन्होंने मुखबिर कहा है, ये साबित करे कि कहां पर किसी ने मुखबिरी की है अंग्रेजों की। ये बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं अगर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण पास हो जाता तो इनकी कुर्सी डगमगा जाएगी- सरिता दुबे, एमआईसी सदस्य

नेता प्रतिपक्ष के ज्ञान में कमी- मेयर

मेयर मीनल चौबे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के ज्ञान में कुछ कमी है। महिलाओं के लिए ये अधिनियम बहुत अच्छा था जो आधी आबादी को मौका दे रहा था शासन की नीति और निर्णय में आने का लेकिन इसे गिराया गया जो शर्मनाक है। इसी को लेकर हमने काली साड़ी पहनकर प्रतिकात्मक विरोध जताया है।

मैं दिनभर नगर निगम में उपलब्ध रहती हूं अगर सार्थक चर्चा चाहते हैं तो वे सादर आमंत्रित हैं, मैं जब उनके जोन में जाकर चर्चा करती हूं तो वे भागमेयर ने कहा कि विपक्ष के सुझावों का स्वागत है साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना जाएगा। निंदा प्रस्ताव के सवाल पर मेयर ने कहा कि सदन निगम के एक्ट के तहत ही चलती है। आज नारी सशक्तिकरण पर ही चर्चा थी।

इसरो के यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में चयनित होने वाली हिमांशी साहू का कलेक्टर ने किया सम्मान

रायपुर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा आयोजित यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में चयनित होकर राज्य का मान बढ़ाने वाली स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कन्नेवाड़ा की छात्रा हिमांशी साहू को बालोद कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने सम्मानित किया। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने आज बालोद के संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कुमारी हिमांशी साहू की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की भूरी-भूरी सराहना करते हुए उनके इस उपलब्धि को पूरे जिले के लिए गौरव बताया। इस अवसर पर कलेक्टर ने हिमांशी साहू को प्रशस्ति पत्र के अलावा शॉल, श्रीफल भेंटकर उनका आत्मीय सम्मान किया।

इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने हिमांशी की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने कुमारी हिमांशी साहू को कड़ी मेहनत कर जीवन में उपलब्धि हासिल करने की सीख भी दी। उल्लेखनीय है कि हिमांशी साहू स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कन्नेवाड़ा में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है। कुमारी हिमांशी ने 96 प्रतिशत अंकों के साथ कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

छात्रा हिमांशी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा आयोजित यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में पूरे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय तथा संपूर्ण बालोद जिला का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने कुमारी हिमांशी के पिता श्री अभय कुमार और माता श्रीमती सहिता साहू को भी सम्मानित कर उनकी सुपुत्री की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, श्री अजय किशोर लकरा एवं श्री नूतन कंवर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

पेयजल आपूर्ति में निगम प्रशासन फेल, अप्रैल में ही गहराया संकट

रायपुर। पेयजल संकट गहरा गया है। रायपुर के अधिकांश इलाकों में नल सूख गए हैं, और टैंकर्स की दौड़ शुरू हो गई है। यह बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि जब अप्रैल माह में ही पेयजल संकट गहरा गया है तो अभी मई और जून भी बचे है, उस समय लोगों का क्या हाल होगा यह तो सिर्फ निगम प्रशासन ही जाने। आम

तौर पर देखा गया है कि शहर में टैंकर की आवश्यकता मई-जून में ज्यादा होती है, क्योंकि इस समय भूजल स्तर काफी नीचे चला जाता है। लेकिन अभी अप्रैल खत्म नहीं हुआ है और आधे शहर का पानी सूख गया है। कई इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से नल भी नहीं खुला है। केंद्र सरकार ने 24 घंटे पेयजल सुविधा प्रदान करने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना तो बड़े जोर-शोर से शुरू की, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लगभग सभी घरों में नल सुविधा का दावा भी कर दिया, लेकिन ज्यादातर नल सूखे हैं। लोग पानी के लिए तरसने लगे है, और इस समय अगर कोई आस है तो वह हैं पानी के टैंकर। अब यह जल संकट जानबूझ कर पैदा किया जा रहा है, या वस्तुत: संकट है, यह कोई तय नहीं कर पा रहा है। चर्चा है कि टैंकर माफियाओं और अफसरों की मिलीभगत से कृत्रिम जल संकट पैदा कर कमाई का धंधा चलाया जा रहा है।

पूर्व सीएम बघेल और महिला के 'फेक एआई वीडियो' पर महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे 'फेक' और 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' आधारित आपत्तिजनक वीडियो के मामले में बड़ा कदम उठाया है। आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने इस पूरे प्रकरण को अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मानते हुए इस पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कृत्य न केवल एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्तित्व की छवि धूमिल करने का प्रयास है, बल्कि इसमें शामिल सामग्री से संपूर्ण महिला समाज की गरिमा को भी गहरी ठेस पहुंची है।

क्या है पूरा मामला?

दिनांक 27.04.2026 को एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित खबर, जिसका शीर्षक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फेक और एआई आधारित वीडियो को लेकर बवाल, एसपी को 02 दिन का अल्टीमेटम है, उसके आधार पर आयोग ने यह कार्रवाई शुरू की है। आयोग के अनुसार, आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्री और एक महिला से संबंधित भ्रामक व आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है।

साइबर सेल की भूमिका- आयोग ने साइबर सेल को पत्र लिखकर वीडियो की गहन तकनीकी जांच करने का निर्देश दिया है। इसमें वीडियो के मूल स्रोत का पता लगाने और इसे वायरल करने वाले गिरोह की पहचान करने को कहा गया है।

एफआईआर और दंडात्मक कार्रवाई- पुलिस अधीक्षक , जिला-दुर्ग को निर्देशित किया गया है कि इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। आयोग ने जोर देकर कहा है कि दोषियों के विरुद्ध ऐसी कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जो डिजिटल अपराध करने वालों के लिए एक नजीर साबित हो। समय सीमा आयोग ने पुलिस प्रशासन और साइबर सेल को की गई पूरी कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट 07 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया है।इस मामले पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए महिला आयोग ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्तियों और महिलाओं के विरुद्ध डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर चरित्र हनन करना एक अक्षम्य अपराध है। आयोग ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि तकनीक का सहारा लेकर किसी की निजता और सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए 13.81 करोड़ की स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु 13.81 करोड़ (तेरह करोड़ इक्यासी लाख पचास हजार रुपये) की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से राज्य के कुल एक हजार 535 अतिथि शिक्षकों को 4-5 माह की अवधि के लिए 20 हजार (बीस हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। वित्त नियंत्रक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलेवार आवंटन के अनुसार बलरामपुर जिले को सर्वाधिक 1.98 करोड़ रुपए अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार कोण्डागांव जिला को 1.27 करोड़ रुपए, बस्तर के लिए 1.20 करोड़ रुपए, सूरजपुर के लिए 1.17 करोड़ रुपए एवं कांकेर के लिए 1.13 करोड़ रुपए की राशि अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। गरियाबंद जिले के लिए 73.80 लाख रुपये, मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर जिले के लिए 70.20 लाख रुपए, सरगुजा के लिए 63.90 लाख रुपए अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। रायगढ़ के लिए 63.00 लाख रुपए, कोरिया के लिए 55.80 लाख रुपए एवं कोरबा के लिए 51.30 लाख) रूपये शामिल हैं।

भाजपा हर वर्ग से टिफिन पर चर्चा करें: शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के टिफिन पर चर्चा अभियान को राजनैतिक नाटक नौटंकी करार देते हुए कहा कि ढाई साल में जनता से किये एक भी वायदे को पूरा नहीं किया, अब टिफिन पर चर्चा करके जनता और अपने ही कार्यकर्ता को ठगने का नया प्लान भाजपा ने बनाया है। प्रदेश

कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि टिफिन में चर्चा के लिए भाजपा कुछ वर्ग चिन्हांकित कर ले और उनके बीच जाकर चर्चा करे। उनसे किये गये वादे पर ढाई साल में सरकार के द्वारा क्या किया गया, उस पर चर्चा कर ले। अनियमित कर्मचारियों से चर्चा कर ले। आंगनबाड़ी बहनों तथा रसोईया संघ तथा मितानिनों से चर्चा कर ले, उनको नियमित क्यों नहीं किया? डीएड के अभ्यर्थियों से चर्चा कर ले, उनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे? युवाओं को बताये 1 लाख नौकरी का क्या हुआ? स्व सहायता समूह की बहनों से चर्चा कर ले, उनका रोजगार क्यों छीना? चाय पर चर्चा के लिए सरकार के पास अनेकों मुद्दे है, जैसे वह अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के तथा पिछड़ा वर्ग के लोगों से चर्चा करे, उन्हें बताये कि पिछले ढाई साल में उनका आरक्षण भाजपा ने क्यों रोक रखा है।

आवेदन को फेंकना छत्तीसगढ़ का अपमान: ठाकुर

रायपुर। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार पर छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे आवेदन को फेंकने की घटना को छत्तीसगढ़ का अपमान करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के ढाई साल में छत्तीसगढ महतारी का निरन्तर अपमान हो रहा है, यहां की बोली, भाखा, परंपरा, संस्कृति को दबाने कुचलने

की साजिश की जा रही है। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार ने छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे आवेदन को फेंक कर तीन करोड़ छत्तीसगढ़ियों को अपमानित किया है। ये निंदनीय है सरकार को तत्काल मुंगेली कलेक्टर पर कार्यवाही करना चाहिए। भाजपा सरकार में दीगर राज्यों की तीज, त्योहार, परम्परा का प्रदेश में जोर-शोर से आयोजन होता है लेकिन जब छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात आती है तो भाजपा का रवैया ढुलमुल रहा है। प्रदेश में अन्य राज्यों के भाषा बोलने वाले है उनका पूरा सम्मान यहां होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा का अपमान सरकार के संरक्षण में उच्च अधिकारी कर रहे है, सरकारी विभागों में भी छत्तीसगढ़ी बोली बोलने वालों को कमतर आंका जाता है। ये बर्दाश्त नहीं की जायेगी। भाजपा सरकार बनने के बाद यहाँ की संस्कृति खतरे में है। आरएसएस की नीति भी स्थानीय संस्कृति को खत्म करने की है।

किसानों की उपजाऊ ज़मीन पर जबरिया खुदाई: वर्मा

रायपुर। राजधानी रायपुर के आरंग ब्लॉक अंतर्गत महानदी के चिखली घाट और समोदा घाट से निजी उद्योग अडानी पावर द्वारा पानी की पाइप लाइन बिछाने किसानों की निजी जमीनों और उपजाऊ खेतों को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि इस गूंगी बहरी सरकार में मोदी के

मित्र अडानी का अत्याचार चरम पर है। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी? महानदी का पानी रायखेड़ा में संचालित अडानी पॉवर प्लांट लाने के लिए किसानो के निजी जमीन, उपजाऊ खेतों में जबरिया खुदाई की जा रही है। मेढ़-पार और हरे भरे पेड़ बेरहमी से काटे जा रहे हैं, अपना खेत पहचानना मुश्किल हो गया है। बिना सूचना दिए, बगैर सहमति 10 फिट गहरा और 10 फिट चौड़ा गड्ढा खोद कर पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। उक्त पाइपलाइन के दोनों तरफ 20- 20 फिट तक की भूमि पर भविष्य में निर्माण प्रतिबंधित रहेगा, कुआं, नलकूप खोदे में भी प्रतिबंध, पेड़ तक लगाने में प्रतिबंध है, यह जानकारी भी किसानों को नहीं दे रहे। फिलिंग के बाद भी 3-4 साल तक खेत के उस भाग में न ट्रैक्टर जा पाएगा न हार्वेस्टर। खेती-किसानी बर्बाद करने पर तुली है कॉर्पोरेट की गुलाम यह अत्याचारी सरकार।

पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे हेतु प्रशिक्षण सम्पन्न

रायपुर। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत संचालित पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो दिवसीय हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित सम्पन्न हुआ। संचालनालय के अधिकारियों ने सर्वेक्षण की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस प्रशिक्षण से प्रतिभागियों की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो सर्वे के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।यह प्रशिक्षण विगत दिनों संचालनालय के प्रशिक्षण कक्ष में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न जिलों से सर्वे कार्य से जुड़े अधिकारी एवं प्रशिक्षुओं ने भागीदारी की। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सर्वेक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया, प्रश्नावली की विस्तृत समझ, डेटा संग्रहण की विधियां तथा फील्ड में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही, हैंड्स-ऑन अभ्यास के माध्यम से प्रतिभागियों को वास्तविक परिस्थितियों में सर्वेक्षण करने का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया गया।

सशक्त नारी, विकसित प्रदेश

'बिहान' से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बनीं सकीना

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे ष्बिहानष् के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह भारत सरकार के दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन कर रहा है। ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं के लिए स्थायी और विविध स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली 'बिहान' (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) योजना महिलाओं के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का बड़ा माध्यम बन रही है। सहारा आजीविका क्लस्टर के उदयपुर विकासखंड के डाड़गांव की रहने वाली

सकीना की कहानी आज अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। जो सकीना कभी बैंक जाने के नाम से घबराती थीं, वे आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से न केवल अपना व्यवसाय संचालित कर रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं।

अभिसरण का कमाल: डीएमएफ मद से मिली मिक्सर मशीन: शासन की विभिन्न योजनाओं के आपसी समन्वय से जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की पहल पर डीएमएफ मद से सीमेंट मिक्सर मशीनें समूहों प्रदान की गई हैं। इन्ही में से एक मशीन 'रामगढ़' ग्राम संगठन के 'साईं बाबा समूह' को मिली, जिसकी सदस्य सकीना हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।निर्माण कार्यों में बढ़ी भागीदारी, बढ़ी आमदनी: सकीना ने बताया कि उन्होंने अपनी आजीविका विस्तार के लिए समूह से 60,000 का ऋण लिया था। समूह को मिली मिक्सर मशीन और शटरिंग प्लेट्स अब उनकी आय का मुख्य जरिया बन गई हैं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों के लिए उनकी मिक्सर मशीन और शटरिंग प्लेट्स की भारी मांग है। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टिंग और अन्य खर्चे निकालकर समूह से अब तक 6,000 से 7,000 की प्रतिदिन की कमाई हो रही है। सकीना अपनी सफलता का श्रेय बिहान योजना को देते हुए कहती हैं, पहले मुझे बैंक जाने में भी डर लगता था, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद मैं जागरूक और सक्रिय हो गई हूँ। अब मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सक्षम हूँ। अब मैं दूसरी दीदियों को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हूँ।सकीना की आर्थिक मजबूती का सीधा असर उनके परिवार पर पड़ा है। उनकी बेटी अब कॉलेज में है और बेटा हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाएं : मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और ग्राम पंचायतवार कार्ययोजना बनाएं। राज्य में जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों के लिए सीएसआर मद की उपलब्ध राशि का उपयोग करना प्रस्तावित करें। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना के लिए गठित स्टियरिंग समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र, राज्य की जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना, राज्य में जलवायु परिवर्तन विषयक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और राज्य जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के गठन और राज्य में कार्बन क्रेडिट आधारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। विभागीय सचिवों से जलवायु परिवर्तन पर कार्ययोजना के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने जलवायु परिवर्तन की पृष्ठ भूमि, जलवायु परिवर्तन के कारक और छत्तीसगढ़ राज्य में भी जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के संबंध में जानकारी दी। बैठक में पीसीसीएफ श्री श्रीनिवास राव, एपीसीसीएफ श्री सुनील मिश्रा शामिल हुए।

वृक्ष-आवरण में देश में प्रथम स्थान पर रहा छत्तीसगढ : छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विविध कार्य किये जा रहें हैं। इनमें मुख्यत: वृक्षारोपण कार्य किये जा रहें हैं। एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत् करीब 7 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.